

to enclose a copy of the Pharmacy (Amendment) Bill, 1976, which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 12th May, 1976."

11.04 hrs.

BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir I lay on the Table of the House the following Bills, as passed by Rajya Sabha:—

- (1) The Marriage Laws (Amendment) Bill, 1976.
- (2) The Tariff Commission (Repeal) Bill, 1976.
- (3) The Merchant Shipping (Amendment) Bill, 1976.
- (4) The Pharmacy (Amendment) Bill, 1976.

11.05 hrs.

FINANCE BILL, 1976—contd.

MR. SPEAKER: The House will now take up further consideration of the Finance Bill for which eleven hours were allotted. Nine hours are already over and two hours are left. The Finance Minister will reply to the debate at 12 O'clock.

श्री हरि सिंह (खुर्जा) : माननीय अध्यक्ष जी, फाइनेंस बिल पर सदन में पिछले कई घंटों से चर्चा चल रही है और यह खुशी की बात है कि भारत का जो अर्थ का भंडार है वह पिछले सालों के मुकाबले में इस बार तेजी से बढ़ा है, और भारत की जो देनदारियाँ थीं, जो कर्ज से लदा हुआ था अब वह हल्का होता हुआ नेजर आ रहा है। अगर आप पिछले सालों के मुकाबले में पिछले वर्ष तथा पिछले वर्ष के आखिरी हिस्से का मुकाबला करें तो आप को प्रसन्नता होगी कि जो आर्थिक संकट देश में था, जो आर्थिक मुसीबत मुल्क

में छाया हुई थी और देश में निराशा का वातावरण था उस पर हमारी सरकार ने अपनी दक्षता से, नई आर्थिक नीतियों से तथा 20 सूत्री कार्यक्रम के जरिये जो छिपा हुआ धन था उसको बाहर निकलवा कर देश के अन्दर एक खुशहाली का वातावरण पैदा किया है। हम देखते हैं कि यह पहला साल है कि हम विदेशों से कर्ज लेने के बदले में अपनी सेवाओं के बदले में तथा अपनी नई नई चीजें विदेशों में भेज कर करोड़ों रुपया और करोड़ों रुपए की मिल्कियत दूसरे देशों से प्राप्त कर रहे हैं। अब तक यह कहा जाता था कि भारत में पेट भरने के लिए नहीं है, बीरों और ईंट की पौलिसी चलती है, लेकिन आज खेती, उद्योग और जीवन के अन्य क्षेत्रों में हमारा आर्थिक ढांचा दिन प्रति दिन सुधरता चला जा रहा है। बड़ी खुशी होती है जब हम यह कहते हैं कि विदेशों को अपना माल भेज कर, रेल के इंजन बाहर भेज कर रुपया वसूल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हमें यह कहने में आज प्रसन्नता होती है कि आज हिन्दुस्तान से एक नहीं सैंकड़ों की तादाद में इंजीनियर्स, डाक्टर्स, प्रोफेसर्स और दूसरे पेशे में काम करने वाले भारतीय लोग विदेशों में जाकर उनके निर्माण में लगे हुए हैं और अपनी सेवाओं के बदले बहुत सारा धन देश में भेजते हैं। तो यह जो वर्ष चल रहा है यह भारत की खुशहाली का एक नया दौर शुरू करने वाला है।

20 सूत्री कार्यक्रम के जरिये देश का जो एक जर्जरित आर्थिक ढांचा था उसको आगे ले जाने में इन सूत्रों ने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान किया है। आज अगर आप सफर करें तो सारे देश में चारों तरफ निर्माण कार्य होते हुए आपको दिखाई देंगे, निर्माण की एक लहर सी दिखाई पड़ती है, चारों तरफ कुछ न कुछ चीज बनती नजर आयेंगी। तो जो हमारा आर्थिक ढांचा है इस वक्त इसकी नींव बड़ी गहरी होती चली जा रही है, और जो देश आर्थिक रूप से अपनी जड़ें मजबूत करेगा वही दुनिया में बड़ा

(जी हरी सिंह)

मुल्क बनेगा। भारत की अबादी, इसका अर्थफल और इसकी अपनी परम्परा तथा संस्कृति बिचस करती है कि हिन्दुस्तान को दुनिया के देशों में एक बड़ा देश बनना है।

अगर आप देखें तो आज हमारे विदेशों से जो ताल्लुकात हैं, पड़ोसी मुल्कों से जो कुछ दिनों से ताल्लुकात बिचड़े हुए थे, उन में आज सुधार आ रहा है और यही नहीं चीन जैसे मुल्क से आज राजनीतिक संबंध हमारे सुधरे हैं। अभी हाल में पाकिस्तान से जो समस्याएँ थीं उनको नए रूप से एक नई जिन्दगी शुरू करने के लिए भवसर दिया गया है।

यह चिन्ता का बिषय है कि फरक्का के इश्यू को लेकर बांग्ला देश और हिन्दुस्तान के जो आपसी ताल्लुकात हैं उनमें तथा दूसरे मुद्दों को लेकर के एक तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। पर हिन्दुस्तान की नीति हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ भ्रमन की रही है, शांति की रही है। वह किसी मुल्क की सीमाओं में घुस कर या किसी मुल्क में तोड़ फोड़ की नीति चला कर उसको अपने प्राधिपत्य में नहीं लेना चाहता है। आप जानते ही हैं कि बांग्ला देश में एक के बाद एक ऐसी घटनाएँ घटीं जिनसे मालूम पड़ता है कि जो बाहर की ताकतें हैं वे बड़ा अन्दर बैठ कर मुल्क में हिंसा का वातावरण पैदा कर रही हैं।

मैं यह कह रहा था कि हिन्दुस्तान वह मुल्क है जो आज अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बड़े सुधरे और ठोस कदम उठा रहा है। आज नई नई चीजें हमारे देश के सामने आती चली जा रही हैं।

मैं जिस जिले से आता हूँ, वह खेतिहर जिला है और वहाँ पर नेह्रू की पैदावार हिन्दुस्तान के किसी एक जिले के मुकामलतन सब से ज्यादा है। पर आप यह देखें कि हमारे जिले में एक आर्थिक संकट आया हुआ है क्योंकि वहाँ के किसान को अपनी नेह्रू की

पैदावार की बहुत सस्ता दरें देना पड़ रहा है और यह भी हो रहा है कि उसको मंडियों से बिरास हो कर चला आना पड़ता है। इसके अलावा उसको बचत पर पैसा नहीं मिल पाता है, उसको समय पर बैंक नहीं मिलता है और अगर बैंक बना भी दिया जाता है तो लिखने में कुछ गलती कर दी जाती है, जिससे बैंक से पैसा मिलने में बहुत समय लग जाता है। इसके अलावा उसका जो भाज होता है, उसको कम तोला जाता है। प्राध्वय-कता इस बात की है कि किसानों को इन्पीट्स दिया जाए क्योंकि अच्छी फसल तैयार कर के वह हिन्दुस्तान को सैल्फ-सफीसिबैली की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन इस बंस्त किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस लिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये जो किसानों की समस्याएँ हैं, इनको हल करने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए।

एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। आज हमारे मुल्क में रुपए की कमी है हालांकि हालत काफी सुधरी है। आपने डाक के टिकटों पर एंडवारटाइजमेंट की मूहर लगा कर कुछ पैसा इकट्ठा करने का विचार किया है। इस सबध में मैं भी एक सुझाव देना चाहता हूँ और वह यह है कि जो बैंक-बुक होती है, जो बैंको द्वारा दी जाती है, यह आम तौर पर सब बैंक मुफ्त में देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप और रुक्या इकट्ठा करना चाहते हैं और आर्थिक संकट को दूर करना चाहते हैं तो जो बैंक बुक दी जाए, वह भी नहीं देनी चाहिए। कुछ न कुछ पैसा जो बैंक-बुक की बुकलेट होती है और जिसमें 20 या 25 बैंक होते हैं, उसके बतूल किए जाने चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस छोटे से प्राइम से देश के अन्दर करोड़ों इन्फ्रा आमदनी हो जाएगी। आखिर बैंक बुक छानने में कुछ पैसा भी खर्च होता है और अगर 10 नए पैसे भी कम से कम रखा जाए तो

काफी आमदनी होगी क्योंकि देश में हर जिले में, हर शहर में और हर एक बिजनेस सेंटर में बैंक इस्तेमाल होते हैं और लाखों की तादाद में बैंकों का आवान-प्रदान होगा है। अगर एक बैंक का काम दो नए बैंक भी रखा जाए, तो इससे मुल्क के खजाने में दसियों करोड़ रुपया आमदनी हो जाएगी। पहली बार मैंने यह आमदनी की आइटम बताई है, जिसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। यह एक ऐसा सोर्स है जिससे किसी को बूझना नहीं पहुंचने वाला है और किसी को ओवरबर्डन किये बगैर यह आमदनी मुल्क को भिन्न सकती है और चाहता है कि सरकार इन और जरूर ध्यान दे।

आज मुल्क के अन्दर-बाहर की निकाशा गया है लेकिन आज भी आमदनी में जो फर्क है, उसको मिटाना चाहिए। आज भी आप देखते हैं कि ऐसे प्रादमों हैं जिनकी योजना की आमदनी लाखों रुपए तक की है और दूसरी तरफ ऐसे भी इन्सान हैं जिनका जीवनयापन भी मुश्किल में होता है। मैं यह कहना चाहता हू कि जब हमारी सरकार ने समाजवाद का लक्ष्य अपने सामने रखा है और उसके लिए वह बड़ी गम्भीरता में कोशिश भी कर रही है और हमारे जो प्लान्स हैं उनके सामने भी यह मवाल है कि इकोनामिक जंजरेशन हो, तो ऐसी हालत में जो धन है, जो दीनत है, वह कुछ हाथों में इकट्ठा न हो और उसका फीनाव हो। इसके लिए हमारी सरकार मतलब प्रयत्न बड़ी गम्भीरता के साथ कर रही है लेकिन मैं यह कहना चाहता हू कि जो आमदनी में फर्क है, उस को मिटाना चाहिये और समाजवाद और समनता के रास्ते में जो यह एक रोडा है, जो आर्थिक असमानता लोगों के बीच में है, यह बहुत बड़ी बीबाव है, इस को समाप्त करना चाहिये।

यही नहीं, आप देखे कि मुल्क के अन्दर ऐसे बहुत से काम घड़े हैं जिन को

लेकर सरकार अपनी आमदनी बड़ा सकती है। जिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी बात आप के सामने रखना चाहता हूँ जिस के लिये सरकार को कोई बहुत प्रयत्न नहीं करना होगा और वह यह है कि, आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि सिगरेट कम्पनियों का रेट आफ प्रोफिट जा है वह 60 फीसवी तक है। इतना बड़ा मार्जिन आप किसी इंडस्ट्री में मुश्किल से पायेंगे। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार में कहना चाहता हूँ कि सिगरेट कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये। यही नहीं कुछ सिगरेट कर्पनिवा तो आज कल हाटलों को भी अपने हाथ में ले रही हैं और नये नये होटल बना कर देश के आर्थिक ढांचे को अपने हाथ में करनी जा रही है। ये छोटा छोटी चीजे हैं लेकिन रोजाना काम में आने वाली हैं। इसलिये मैं सरकार में निवेदन करूंगा कि वह सिगरेट कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करे और उन को अपने हाथ में ले ले। इसमें बेहतरीन सिगरेट लोगों को पीने में मिलेगा और वे मस्ती भी होंगी।

चीनी मिलों के बारे में बहुत दिनों से बात चल रही है। आप देखे कि शुगर मिलों पर लाखों करोड़ों रुपये का कर्ज है और कोई चारा नहीं निकल पा रहा है, कोई माध्यम नहीं निकल रहा है कि वह बसूल हो। किसानों का काफी रुपया शुगर मिलों पर बकाया है लेकिन वह उन को मिल नहीं पा रहा है। इसलिए उन का राष्ट्रीयकरण तो हाना ही चाहिये लेकिन साथ ही साथ मैं यह चाहूंगा कि जिन मिलों ने इस इंडस्ट्री को चलाया था, उन के घरों पर जो धन दीनत है, उन को भी सरकार को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए क्योंकि धन दीनत बसा कर वे लोग तो अलग हो गये और अब उन की टूटी फूटी मिलें पड़ी हुई हैं और उन को वे सरकार को

सौमन्य चाहते हैं। इसलिये जूनर बिजों का राष्ट्रीयकरण करने के साथ साथ जो परिवर्धन बीबी मिल बसते थे; उनके बरों से पैसा बचाने करना चाहिये क्योंकि आज किसानों से उन बीबी मिलों से पैसा नहीं मिल पाता है।

अन्त में मैं यह कहूँगा कि सरकार ने जो आर्थिक कदम उठाये हैं, उनकी भी प्रशंसा करता हूँ और इस फाइनेंस बिल के पास किये जाने का अनुमोदन करता हूँ।

श्री कृष्णलाल प्रसाद (महडोल) माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल मंत्री महोदय ने इस वर्ष जो बजट प्रस्तुत किया है, उस में जो मथारबादी दृष्टिकोण अपनाया गया है और वर्तमान परिस्थितियों में सरकार ने जो कदम उठाये हैं, उन का मैं स्वागत करता हूँ। इस सारे देश में सर्वत्र सन्तोष व्यक्त किया जा रहा है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में जो राहत दी गई है, इसकी सबों ने सराहना की है। केन्द्रीय सरकार प्रशासनिक खर्च में कमी करने में सफल हुई है। खाद्यान्न की व्यवस्था सुधरी है, मुद्रा स्थिति में रुकावट आई है। यह आस्टीरिटी का प्रमाण है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि देश की अर्थ-व्यवस्था को नियंत्रण में करने के लिए हम से सहायता मिला है और इस आस्टीरिटी से जीवन-उपयोगी वस्तुओं की कमी की पूर्ति हुई है और उन की कीमतों में गिरावट आई है।

हमारे देश में आदिवासियों की समस्या आज बहुत बढ़ी है और उन के विकास के लिए और अधिक प्रयत्न करने चाहिए। इन का विकास क्षेत्र के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आदिवासी क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन के लिए छोटे छोटे काम छोटे-छोटे शुरू करने के लिए

दोनों काय, जिन सहायता मिलती परीक्ष। वहाँ तक देना संभव का सम्बन्ध है, यह मेरे क्षेत्र से जना हुआ है और वहाँ पर आज सागर निर्माण की योजना है। यह अभी तक नहीं हो सका। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि वहाँ पर जिन की सुविधाएँ, विविधताएँ, उद्योग और सिंचाई के सामान जुटाये जाएँ।

समापति महोदय जी हमें देश को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए आदिवासी और कमजोर वर्ग के लोगों की आर्थिक दशा सुधारनी होगी। आदिवासी क्षेत्रों के विकास का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति गांवों से कर सकें। ऐसा होने पर ही उनकी संस्कृति, रीतिरिवाजों, लोक कलाओं एवं अन्य विशेषताओं का विकास होगा।

भारत की परिस्थितियों को देखकर ही महात्मा गांधी ने कहा था कि हम गांव की ओर चलें। इस प्रकार हमें गांव की ओर चल कर ऐसी योजनाओं का निर्माण करना है जिससे देश के कई भागों में बसे आदिवासियों का विकास हो। आदिवासियों के विकास के लिए हमें एक पृथक योजना प्रायोग बनाने की आवश्यकता है। हमारा यह प्रयत्न होना चाहिए कि गांव में रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि हो और उनके रोजगार साधन बढ़ें।

कोयला खानों और उनमें काम करने वाले मजदूरों से मेरा गहरा सम्बन्ध है। खान मजदूरों की सुरक्षा पर अधिक ध्यान की आवश्यकता है। जो अधिकारी इस विषय में लापरवाही बरतते हैं, उन्हें कड़ी सजा दिया जाना चाहिए। खानों में काम करने वाले श्रमिकों की दशा में सुधार करने की भी जरूरत है। उनकी मजदूरी में सुधार हो, उनके हलाक आदि की सच्ची व्यवस्था

हूँ। इन भूमिकों की पारिवारिक बंशज प्रतिभवा बीमा प्राप्ति के विषय में जो फन उठाये गये हैं, वे स्वागत योग्य हैं।

सभापति जी, हमारे देश में बाजार उत्पादन को अधिक विकसित बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में गरीब किसानों को अधिकतम सुविधाएँ देने का जो मौलिक उद्देश्य है या बनाया जा रहा है, यह कल्याणकारी है। उपभोक्तानों की जरूरतों के लिए सरकार जो कदम उठा रही है, वह भी स्वागत योग्य है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा ऐसा प्रयत्न होना चाहिए जिससे प्राद्विवासी क्षेत्रों में जो छोटे छोटे किसान हैं, या अन्य श्रमिक हैं उन्हें जरूरतों की चीजें सस्ते दामों पर उन्हीं क्षेत्रों में उपलब्ध हो सकें। सरकार उपभोक्ता की जरूरतों और उत्पादन दोनों पर दृष्टि रख रही है यह एक यथार्थवादी दृष्टिकोण है।

कृषि पर हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। कृषि उपज को खरीदने के लिये विमोच निगम की स्थापना हीनी चाहिए। देश में आज छोटे-छोटे ट्रक्टरों की आवश्यकता है। जिसकी छोटे-छोटे किसान भी खरीद सकें। देश में किसानों को खैरि सम्पन्धी महत्ता देने के लिए छोटे छोटे केन्द्रों का जाल बिछाया जाना चाहिये। कृषि मूल्य संयोजन ने उपयोगी कार्य किया है। किन्तु इसका कार्य क्षेत्र विस्तृत हो जिससे यह व्यापक रूप से कार्य कर सके।

सरकार के विमोच प्रयत्न से आज पूरे देश का वातावरण अधिक शान्त है। इसे मैं औद्योगिक शान्ति का उदय ही कह सकता हूँ।

अन्त में मैं वित्त विधेयक का समर्थन करते हुए बजट को एक कल्याणकारी कदम मान कर बधाई चाहता हूँ कि जिस प्रकार

आजादी की लड़ाई के दौरान नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने देश की जनता को प्रेरित किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा, उसी प्रकार हमारी प्रधान मंत्री जी ने भी देश की जनता का आह्वान किया है कि तुम मुझे सहयोग दो, मैं तुम्हें महान कल्याण दूँगा। इस प्रकार देश को महान बनाने का कार्य ऐसे ही कल्याणकारी बजट से हो सकेगा।

श्री जति भूषण : (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने देश की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाया। हमारे देश की रुपये की प्रतिष्ठा बढ़ी है। यह विदेशों में बहुत बढ़ी है इससे हमारे देश में निर्माण कार्य तेजी से हुआ है और फाइनेशियल इस्टीमेटयूजस बहुत सजग होकर काम कर रहे हैं। अभी एमर्जेन्सी को एक साल हुआ है। इतने थोड़े अर्थ में इतनी तरक्की हुई है तो मैं आपसे दक्षिण करूँगा कि इस एमर्जेन्सी को दस साल और रखा जाए। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय जिनकी कुन्द बुद्धि हो, उनकी समझ में यह बात नहीं आ सकती, न मैं उन्हें समझाने का प्रयत्न करूँगा। इतने थोड़े से प्रयत्न से देश में डिस्सिप्लीन आ गया है, प्रोडक्शन बढ़ गया है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में 25 हजार करोड़ रुपये का सोना लोगों ने जमीन में गाड़ रखा है। अगर वित्त मंत्री जी किसी तरह से उस सोने को निकाल सकें तो हमारे देश का अधिक निर्माण हो सकेगा। सोने से लोगों को मोहब्बत है, प्रेम है। लेकिन अगर मुक्त सञ्चय नहीं है तो वह सोना कई बार देश से बाहर भी चला जा सकता है। जिन लोगों ने यह सोना रखा हुआ है, वे समाज के दुश्मन हैं। सोना धाम आदर्श के पास तो होता नहीं। जिनके पास सोना है उनसे विचलने का प्रयत्न

[श्री सति भूषण]

फिन्स बिजनेस + आप जानते हैं कि देश में वस्तु-व्यापार करोड़ों रुपयों का मरिचक है और पच्चीस हजार करोड़ रुपये का सीमा क्षेत्र में गड़ा हुआ है। पिछले दिनों आपने ज्वैक का कुछ रुपया निकाला भी है और निकालने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। इस सीमा को भी आप निकाल सकें तो देश में निर्माण कार्य आप तेजी से कर सकते हैं।

अध्यक्ष जी, हमारे देश में एक करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं, सेना में, रेलवे में, और 25 लाख तो हमारे मित्रक ही हैं। इस तरह से ये एक करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं। एक करोड़ अग्र मिडिल क्लास के एप्रीकल्चरिस्ट्स हैं जिनके पास ट्रेक्टर हैं और सिखे हैं वे माधन हैं। एक करोड़ इस देश में ऐसे आदमी हैं जो सस्ता मास खाते हैं और महंगा बेचते हैं। सुबह से शाम तक यही काम करते हैं। एक करोड़ ऐसे लोग हैं, मिस्त्री या मिस्त्री के ऊपर के, जिन्हें स्किन्ड लेबर कहा जाता है। ऊपर से नीचे तक ये चार करोड़ लोग काम करने हैं। इन चार करोड़ लोगों पर पांच पांच आदमी निर्भर करते हैं और बाकी भारत होता है।

मैं मूरत की बात आपको बताता हूँ। मूरत के क्षेत्र में वन मीनिंगन लेण्डनेस लेबरर्स हैं। उनकी यूनिनन ने पाम कर दिया कि पांच रुपये से कम मजदूरी नहीं लगे। वहाँ की पिछली सरकार ने भी पास कर दिया था। लेकिन वहाँ के लोकल जमींदारों ने यह फैसला कर लिया कि वे लोकल लेबरर्स से काम नहीं लगे। एक रुपये रोज पर वे महाराष्ट्र से लेबरर इम्पोर्ट करके ले आते हैं और मूरत के एक मिलियन लेबरर की हासत

पूर्वों मरते की हो गयी है। बीस सौ प्रोबान में अगरे इन चीजों को काय करना है तो जो लैण्डनेस लेबरर्स के लिए मिनिमम बेज हमने तय किया है, उसको लागू करवाने के काम को भी सरकार इस तरीके से अपने हाथ में ले जिससे कि ये बड़े लोग उन पर हावी न हो सकें। उनके माथ भी सही सख्ती की जाय जो एक्ट्यूटर के साथ की गयी, ज्वैक मॉर्फिटियर्स के साथ की गयी, करप्शन करने वालों के साथ की गयी। जो लोग मिनिमम बेज नहीं देते हैं, उनको भी मीमा में बन्द किया जाय। ज्यादा लोगों को आपकी बन्द नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारे लोग तो हमसे वैसे ही भय खा जायेंगे। इस तरह से अगर आप इस दिशा में प्रयत्न करेंगे तो लैण्डनेस लेबरर्स को मिनिमम बेज प्राप्त दिला सकेंगे। आजकल पञ्जाब और उत्तर पू० पी० में तो थोड़ा अधिक पैसा लैण्डनेस लेबरर्स को मिल जाता है। लेकिन मैं गुजरात और मध्य प्रदेश की बात कह रहा हूँ जहाँ एक रुपये से ज्यादा मिनिमम बेज नहीं दिया जाता।

अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में चार करोड़ आदमी ऐसे हैं जो मेहनत करके दीलत पैदा करते हैं। अगर सब लोगों को दीलत पैदा करने का मौका दिया जाय तो देश बहुत समृद्ध हो सकता है। हमारे देश में सब कुछ है, पेट्रोल है, लोहा है, सीमेंट है, आदमी है, हाथ हैं और शक्ति है। अगर हम इन सब का उपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम दिया जाय तो देश बहुत समृद्ध हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, लगभग दस मिलियन टन जंगल की लकड़ी इस देश में बाँटें में जला दी जाती है। बड़े बड़े शहरों में लकड़ी जलाने पर रोक लगनी चाहिए। बड़े शहरों में इसको ठोका ढोय और कोयला जलाना कम्पलसरी किया जाय। इस

संरक्षित करीबना निकालने के काम में ज्यादा लक्ष्यपूर्वक लक्ष्य और कोयले का ज्यादा प्रोत्साहन बढ़ाना होगा। सहरी में लकड़ी लाने पर कुछ न कुछ बंदिख लगायी जाय। गांवों में जाऊ बरीबी है, वहां हम क्रयें नहीं पहुंचा सकते हैं। जैसे तो हिन्दुस्तान बहुत गरीब देश है लेकिन हमारे देश में क्रय का सबसे ज्यादा संजमन होता है। दुनिया में कहीं इतना नहीं होता। हमारे यहां 8-8 बंदे महिला रोटी बनाती रहती हैं। इस देश में हमें अपनी क्रय हैबिट्स को बदलना होगा। जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है उनको देखते हुए हमें यह करना होगा। हमें हर पांच लाख की आबादी पर एक आटा मिल और एक बेकरी बनानी चाहिए। सारी दुनिया में—चाहे मोवियल संघ हो, चाइना हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, सब जगह सस्ती रोटी बना कर लोगों को मुहैया की जाती है। अपने देश में भी हमें ऐसे कदम उठाने होंगे और लोगों की क्रय हैबिट्स को बदलना होगा। क्रय संजमन को भी हम चेनेलाइज करना होगा। अभी से इस दिशा में हम काम करेंगे तो एमजॉसी के दौरान हम लोगों की क्रय हैबिट्स को, सोशल हैबिट्स को—सोने की हैबिट्स को—बदल सकेंगे और अधिक से अधिक लोगों को काम दे सकेंगे। अभी से इस दिशा में चलने का हमें प्रयत्न करना चाहिए।

बस इतना ही मैं दरखास्त करना चाहता हूँ।

*SHRI E. R. KRISHNAN (Salem):
Hon. Mr. Speaker, Sir, on behalf of the Anna D.M.K., I rise to express my views on the Finance Bill. I have to point out that the Annual Budget presented before this House by the Hon. Finance Minister for the year 1976-77 and the Finance Bill now under discussion would contribute greatly to the success of the 20-point economic programme of our

respected Prime Minister. I need not stress the fact that these two are the potent instruments for effective implementation of the 20-point economic programme. I pay my compliments to the hon. Finance Minister for having formulated such a Budget and Finance Bill which would help in the successful implementation of the 20-point economic programme.

When the country was going through a raging inflation, when the prices of essential commodities were soaring, the hon. Finance Minister had in fact performed a miracle through the current year's Budget. The fiscal measures he has adopted have contained both inflation and soaring prices. The other day the hon. Finance Minister announced concessions amounting to Rs. 9.90 crores in the interest of economic growth of the country. On behalf of A.D. M.K., I pay my humble tributes to the sagacity of our Finance Minister in having presented such a constructive Budget and Finance Bill which have helped greatly the economic growth.

It has been the normal feature that the hon. Finance Minister and the Finance Ministry become the target of attack of all the political parties and also the common people whenever the agricultural production or the industrial production receives a set back. This year it is heartening that both the agricultural production and the industrial production have gone up beyond expectations. The days of scarcity have been replaced by the days of plenty. The fertiliser production this year has gone up so high that there seems to be no buyer; Rs. 100 crores worth of fertilisers are lying stagnant. Many crores worth of handloom cloth, mill cloth are going abegging. The steel production has achieved unprecedented

[Shri E. R. Kashman]

record. It has to be welcomed that production in all the sectors has gone up during this year.

Sir, I would like to suggest a new thing in regard to agriculture. Instead of clamouring for agricultural sector, it must be ensured that the agriculturists get much required incentives. The Government must give them free of cost all the inputs of agriculture—electricity, improved variety of seeds, fertilisers, insecticides, pesticides etc. and in return the Government may take one-third or one-fourth of the agricultural produce. If this is done, all the major problems confronting the agriculturists would disappear and consequently the agricultural production would go up. The agriculturists would never lament that they have not got seeds, no fertilisers etc. I understand that such a system is prevalent in some foreign countries. I would appeal to the hon. Finance Minister to examine this proposition seriously.

Many hon. Members had demanded that the maximum rate of incometax should be brought down. I am happy that this year the hon. Finance Minister has brought down the maximum rate of incometax to 66 per cent. This will generate greater investment in industries. The entrepreneurs will no doubt avail of these incentives and come forward to set up new industrial establishments. It is heartening that the Government realised the urgent need for industrial growth and has given this incentive to the industrial entrepreneurs.

There has also been persistent demand on the floor of this House that the exemption limit for income-tax should be raised from Rs. 8000 to Rs. 12000. The Minister of State, Shri Pranab Mukherjee, stated that it would not be possible for the Government to raise the income-tax exemption limit from Rs. 8000 to Rs. 12000.

He pointed out that out of the total population of 80 crores only 30 lakh people are assessable now. I would like to point out that if the income-tax exemption limit is raised from Rs. 8000 to Rs. 12000 there is the possibility of the number of assesses going up to one crore. There will also be less of incometax evasion. The Department will be able to concentrate their efforts on the large assesses, which will lead to greater revenue for the Government. Here, this must also be borne in mind that the value of rupee in 1955 was on rupee four paise and in 1975 it was only 26 paise. In these circumstances, there is imperative need for raising the income tax exemption limit from Rs. 8000/- to Rs. 12000/-.

Sir, one of the basic reasons for the fall in prices was the Voluntary Disclosure scheme under which a total sum of Rs. 1580 crores was declared; to that extent the black money circulation was reduced. Everyone expected that the disclosures would net exceed Rs. 1000 crores. But the disclosures reached Rs. 1580 crores surpassing all the calculations. This helped greatly in the fall of prices and also in the containment of inflation. If the raids and seizures are intensified in the current year also and if the hidden wealth is declared openly to the extent of Rs. 3000 crores, then it will be a permanent solution for holding the price line; it will also curb the inflationary tendencies for ever. I am sure that the hon. Finance Minister will look into this matter with this background.

If the Government want to eliminate black money from the economic scene of our country, then the export trade should be nationalised. This will end for ever the personal malpractices like over-invoicing and under-invoicing. The quantity of our export commodities will also be not a victim of vitriolic criticism abroad. In other words, the quality of our exports will be upto international standards.

Recently, the Reserve Bank has directed that the dividend declared by the Banks on their shares should not be beyond 12 per cent. This ceiling has acted as a disincentive for the prospective buyers of shares. This will also lead to a steep fall in Bank deposits. I suggest that this ceiling of 12 per cent should be raised further in order to attract more Bank deposits and more buyers of shares. If the Bank deposits go up, naturally that will be used for production purposes, leading to accelerated economic growth.

Sir, if the 20-point economic programme of our Prime Minister is to succeed throughout the country, then the masses of our country must be made aware of the contents and benefits of this 20-point economic programme. I am afraid that the Government's effort in this direction is tardy. The entire population of our country must know what this 20-point economic programme means for their life. This programme must also be implemented in all the States in a uniform manner avoiding any lop-sided benefits to certain sections. The power and irrigation must be in the central sector. All the rivers should be declared as national rivers. The generation of electricity must also be the central responsibility. If the rivers are nationalised, the river-water disputes between the States will be done with. The nation's prosperity lies in this.

Many hon. Members have pointed out that the rural people do not get easy financial credit for meeting their needs. The Central Government must ensure that there is a cooperative Bank or a commercial bank in each Panchayat catering to the financial needs of the farmers. Such banks should be authorised to give loans against the golden and silver jewellery belonging to these people. I mean to say that they should get credit facilities quickly without being harassed by so many procedures.

Now that Tamil Nadu is under President's rule, now that Tamil Nadu is

being administered by the Governor under the directions of the Central Government, I have to point out certain things which are to be done immediately. The hon. Finance Minister of the Government of India is keen to help the people of Tamil Nadu. The Central Government as a whole want to help the economic needs of Tamil Nadu. In these circumstances, I want to appeal to the hon. Minister of Finance that the basic minimum requirement of Rs. 16.5 crores this year for the Salem Steel plant, the foundation-stone for which was laid by the hon. Prime Minister in 1970, should be sanctioned. I regret to say that only Rs. 3 crores has been sanctioned in this Budget. Rs. 16.5 crores is the minimum requirement of Salem Steel Plant this year. This must be sanctioned. Similarly, the Central Government must expedite the completion of Salem Steel Plant which is the long-cheshed dream of the people of Tamil Nadu. Besides this, for the economic development of Tamil Nadu, the Sethusamudram Canal Project, the Naivelli Thermal Plant, the Kalpakkam Atomic Power Plant must be completed at the earliest.

Before I resume my seat, I would like to say that my party, the Anna Dravida Munnetra Kazhagam will actively participate in the successful implementation of 20-point economic programme of our Prime Minister in Tamil Nadu.

श्री राज सहस्र बंधे (राजनदगांव) :

प्रधन जी, आज ही समाचार-पत्र में यह है कि विश्व बैंक ने हमारी वार्षिक स्थिति का जायजा लेते हुए बड़ी भास्वा प्रकट की है और यह कहा है कि दुनिया के लगाने देशों में भारत एक ऐसा देश है, जिसने मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कर लिया है, जहां बाजारों के भाव कम हुए हैं, जहां उत्पादन बढ़ा है। अब संसार के बैंक से, उसके कानसाक्षिक के माध्यम से हमको महत्व मिलता है तो यह एक बड़ा संतोषजनक चित्र हमारे सामने

[श्री राम सहय पांडे]

उपस्थित होता है, जिससे हमें उत्साह मिलता है।

वह वर्ष उपलब्धियों का वर्ष है। ऐसा लगता है कि इस वर्ष कुछ बदले हुए वातावरण में, कुछ परिवर्तित स्थिति में, शांतिपूर्वक या अनुशासन-पूर्वक की संज्ञा देकर, देश में आर्थिक उन्नति व प्रगति के लिये बड़ी कार्रियसनेस दिखाई पड़ती है। श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में, देश के आर्थिक विकास के लिये उनके द्वारा दिये गये 20-आचरण, 20-सूत्री कार्यक्रम को सारे के सारे देश में एक स्वर में स्वीकार किया गया है, आस्था प्रकट की गई है और उस पर आचरण करना आरम्भ किया गया है। उसी का यह परिणाम है कि औद्योगिक क्षेत्र में भी उत्पादन बढ़ा है, खेती के क्षेत्र में भी उत्पादन बढ़ा है। उत्पादन के जितने उपकरण थे, उन सब में भी उत्पादन बढ़ा है।

अगर समाजवाद के मार्ग पर हमें जाना होगा, तो जो भी हमारे कमिटमेंट्स हैं, उनको पूरा करना होगा। यह उत्पादन प्रधान है, अगर उत्पादन नहीं होगा तो हम अपने वायदों को पूरा नहीं कर सकते।

श्री सुब्रह्मण्यम जी ने अब की बार, शायद पहली बार अपने फाइनेंस बजट में कुछ प्राथमिकताएं प्रायटीज दी हैं। उन्होंने रूल इन्ट्रिग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम की एक पुस्तिका तैयार की है जिसे उन्होंने यह कल्पना की है कि हमारी धरती, पानी, खेती के उपकरण, आधुनिकीकरण और जितनी उसकी सामग्री है उसकी साइटिफिक एप्रोच बैज्ञानिक दृष्टिकोण कौन होना चाहिए और हम जागृति के लिये 15 करोड़ रुपये का प्रावधान उन्होंने किया है। क्योंकि अब खेती का शरीर से ही सम्बन्ध तही है उसका सम्बन्ध मस्तिष्क-विज्ञान से बन गया है और इसके लिए प्रायटिज में पानी हाई-बीड

कीज-क्रिटिलाइजर पंस्टीसाइड्स हत्यादि उनमें का प्रावधान किया गया है। इसके साथ-साथ यह भी प्रावधान किया गया है कि इसकी विशासता हो, इसकी जानकारी होगी और पूरी मालूमता हो। उन्होंने जो यह कार्रियसनेस और प्रति इन्ट्रिग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम के द्वारा दी है और 15 करोड़ रुपये का प्रावधान इसके लिए किया है इस सम्बन्ध में श्री महोदय बघाई के पास है।

इसका मतलब यह है कि अब जितना पानी हमारे देश में है उसे खेती की सिंचाई की और उन्मुख करना चाहते हैं। हमारे देश में पानी की कमी नहीं है। संसार का 1/10 पानी हमारे देश में है बहुत-सी रिजर्व है। बहुत-सी रिजर्व का झण्डा है। मैं निवेदन करना चाहता हू कि नदियों के झण्डे का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। यह राष्ट्रीय सम्पत्ति है। जब आप इन्ट्रिग्रेटेड डेवलपमेंट की बात सोचते हैं तो पानी जिसे प्रावधानता की कक्षा में रखा जा सकता है वहां पर आप देखें कि कोई झण्डा न हो और जो भी निर्णय केन्द्र कर दे उसे सबकी मानना चाहिए। जितने भी विवाद हैं वे सब दूर होने चाहिये।

आपने कहा है कि हमको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाकर खेती का उत्पादन के माध्यम से जो बड़ा की लोकल पापुलेशन है वहां के यूथ हैं उनको उनमें लगाना है यह एक बड़ा अच्छा कन्सीशन है। क्योंकि नगरों का जो बढ़ना है और उनमें स्लम का बढ़ना इसी कारण है कि सारे के सारे नौजवान शहर की तरफ भागते हैं। अगर लोकल इंडीजिनस, छोटे-छोटे उद्योगों के माध्यम से इन्फ्रा-स्ट्रक्चर देकर उनको वहीं रोक दे वही उनको काम दे तो यह एक बड़ी अच्छी बात है, जो कि आपने सोची है लेकिन इसके पहले उनको टेकिनबल नो-हाउ आदि सब बनाना चाहिए और जितने आपके पास साधन हैं वह सब के सब ताब की तरफ आने चाहिये। अब बम्बई, कलकत्ता मद्रास, दिल्ली,

या करीबबाद के बिना पूरे हो चुके हैं, वहाँ बड़ा कंसट्रेशन, केंद्रीकरण ही गया है। ज़मीनों का धब तो देहात की तरफ बढ़ना चाहिए। छोटे-छोटे उद्योगों के प्रति यह बात आपके मन में है, यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन वह नहीं होना चाहिए कि इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी के कारण हम बेकार रहे। हमें भोजन के बाव बेकारी भी दूर करनी है। बेकारबेकारी दूर करेंगे तभी भोजन दे सकेंगे। भोजन और काम प्रायः पर्यायवाची शब्द हैं संज्ञा है, जो साथ-साथ चलते हैं। आपको इस तरह बड़ी सतर्कता के साथ और जागृती के साथ कर्त्तव्य बढ़ाने चाहिए।

आपको यह वर्ष उपलब्धि का वर्ष रहा है। धन स्टीम, सीमेंट, इंजीनियरिंग गडज और टैक्निकल नो-हाउ यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ड्रेड ईलैंस भी पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष अच्छे हैं और इस कारण जो विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं, वह भी बहुत ठीक है।

एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो इंडियन एंटरिजन के लोग विदेशों में जाकर बस गये हैं, उनमें द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करके यहां भेजने का जो प्रावधान किया गया है, जो सुविधायी दी है, मैं अभी सियापुर में था वहां के व्यापारियों ने उसकी बड़ी सराहना की है। जो पैसा वहां रका हुआ था, वह अब विदेशी मुद्रा में ही यहां जमा किया जा सकता है और उसका उपयोग भी विदेशी मुद्रा में बाहर कर सकते हैं। इस तरह से विदेशी मुद्रा आई है और उसका स्वागत किया गया है।

सबसे बड़ा प्रश्न हमारे देश में अनाज का था। आपने दो-तीन वर्ष की स्थिति देखी है। मैंने मध्य प्रदेश से देखा कि दाने-दाने के लिए हमारे गांवों में लोग तड़प गए। छत्तीसगढ़ की स्थिति ऐसी है कि अगर पानी होना तो खेती होगी, धान होगा, अगर पानी नहीं होगा तो सूखा होगा। रबी की फ़ाय में

तो यह होता है कि पानी कम भी हुआ तो कुछ न कुछ उगा लेते हैं, लेकिन अगर धान की खेती में पानी नहीं होगा तो बिल्कुल सूखा पड़ेगा। 2-3 वर्ष के कठिन काल के बाद यह वर्ष अच्छा हुआ है और छत्तीसगढ़ में अनाज अच्छा हुआ है।

मेरा निवेदन यह है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जो एलोकेशन करने हैं, उसमें पॉर्टेबिल को भी देखना चाहिए। हमारे यहां नर्मदा प्रधान नदी है, उसके अलावा और भी बहुत सी नदियां हैं, पानी हमारे यहां है, लेकिन सिंचाई का प्रतिशत पंजाब और हरियाणा के मुकाबले बहुत कम है। यह 8 प्रतिशत के करीब है। इस 8 प्रतिशत की सिंचाई से हम तमाम मध्य प्रदेश को खिला नहीं सकते हैं। नदियों के पानी का एलोकेशन अगर आप एरिया की दृष्टि से करें, पॉर्टेबिल और प्रोडक्शन को देखकर करें तो हम खेती का विकास ज्यादा तेजी से कर सकते हैं, उत्पादन की दृष्टि से आगे बढ़ सकते हैं।

मैं फिर इस बात को दोहराते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि इस 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जो मार्गदर्शन हमको मिला है, जो रोशनी मिली है, जिस प्रकार आपने एक प्रैक्टिकल बजट रखा है, और समूचे देश की स्वोक्ति प्राप्त की है, एक कांशियसनेस पैदा की है, जागृती की है और उत्पादन ओरिएन्टेड दिमाग पैदा करने की कोशिश की है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।

श्री राम बेब सिंह (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, फिनांस बिल पर बहस के दौरान माननीय सदस्यों ने देश की प्रगति और कृषि के विकास पर काफी संतोष प्रकट किया है। मैं उनकी बताना चाहता हूँ कि गांधी जी कहा करते थे कि जब स्वराज्य होगा तो वह गांधी में आयेगा। इसलिए मैं

[श्री राम देव सिंह]

माननीय सदस्यों का ध्यान गांवों की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

मंत्री महोदय किसी भी गांव में चले और वह अपने साथ अर्थ-शास्त्रियों की एक टोली ले लें, जो इस बात का सर्वे करे कि आज से बीस, पच्चीस साल पहले गांवों की जो स्थिति थी, क्या उसमें कोई सुधार हुआ है। तथ्य यह है कि आज भी गांवों में वही टूटी-फूटी सड़कें हैं, वही अंधकार है, वही अशिक्षा और बेकारी है, वही पुलिस का जुल्म और घूसखोरी है और जनता में वही भय का वातावरण है।

सरकार भले ही कितना ढिंढ़ोरा पीटे कि उसने गांवों के लोगों और किसानों के रहन-सहन के स्तर में उन्नति की है, भले ही विश्व बैंक ने सरकार के कार्यों की कितनी प्रशंसा की हो, लेकिन मेरा टेस्ट तो गांवों की वास्तविक स्थिति है—अगर वहां के लोगों के जीवन में कोई उन्नति नहीं हुई है, तो सरकार के प्रचार और प्रशंसा का कोई महत्व नहीं है।

यह ठीक है कि कृषि की पैदावार बढ़ी है। लेकिन क्या वह इमर्जेंसी के कारण बढ़ी है? जब से सरकार देश की छाती पर तलवार ले कर बैठी है, क्या वह तब से बढ़ी है? क्या यह क्रम 1967-68 के बाद से शुरू नहीं हो गया था? जब इस देश में भयंकर सूखा और किसानों में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई, तब उसने किसानों को मेहनत करने और पानी पैदावार को बढ़ाने के लिए झक झोर दिया। यह ठीक है कि सरकार ने कुछ साधन उपलब्ध कराये, कृषि का विकास हुआ और पैदावार बढ़ी, लेकिन आज किसानों को अपनी पैदावार की कीमत क्या मिल रही है? सरकार उनको गेहूं की कीमत 105 रुपए प्रतिक्वंटल देती है। लोहे और सीमेंट की पैदावार भी बढ़ी है, लेकिन आज लोहे, सीमेंट और पम्पिंग सैट आदि की कीमत क्या

है? 500 रुपए में बिकने वाला पम्पिंग सैट आज 5500 रुपए और 6,000 रुपए में बिक रहा है। 9,000 रुपए या 10,000 रुपए में बिकने वाला जेटर ट्रैक्टर आज 46,000 रुपए में बिक रहा है।

सरकार की तरफ से बड़ा संतोष प्रकट किया जाता है कि चीजों की कीमतों में ह्रास हुआ है। मगर कल-कारखानों में बनी हुई वस्तुओं की कीमतों में किसी तरह का ह्रास नहीं हुआ है। अगर ह्रास हुआ है, तो इस देश के अन्नदाता, इस देश के प्राण, गांवों के किसान ने जो पैदावार बढ़ाई, उसकी कीमत को सरकार ने घटाया है। पन्तनगर एग््री-कल्चरल यूनिवर्सिटी ने बताया है कि एक क्विंटल गेहूं पैदा करने के लिए किसान को 105 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन सरकार उसको उतनी भी कीमत नहीं देती है। किसान जब अपना गेहूं बेच कर सिंचाई के लिए पम्पिंग सैट, या घर बनाने के लिए सीमेंट, या खुरपी और कुदाल बनाने के लिए लोहा लेने के लिए जाता है, तो उसको कहीं अधिक पैसा देना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण आने वाले ढाई तीन बरसों में लगभग 30 परसेंट किसान अपने खेतों को बेच कर शहरों की ओर जाने वाले हैं।

सरकार की तरफ से कहा जाता है कि 20-सूत्री कार्यक्रम एक प्रगतिशील प्रोग्राम है। इस बात को कौन नहीं मानता है? लेकिन यह 20-सूत्री कार्यक्रम एक दिखावा मात्र बन कर रह गया है। आप चल कर किसी थाने के दरोगा या किसी जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के चरित्र को देखिए अगर उसमें किसी तरह का सुधार हुआ हो, तो मैं सरकार की बात को मान लूंगा।

मैंने तो 20-सूत्री कार्यक्रम को एक सूत्र में बांध दिया है और वह एक सूत्र यह है कि आदमी को कर्त्तव्यनिष्ठ होना चाहिए।

अगर आदमी कर्तव्यनिष्ठ होगा, तो वह अनुशासित, दूरदर्शी और मेहनती होगा। क्या सरकार ने देश में कर्तव्यनिष्ठ नागरिक पैदा किये हैं? क्या उसने लोगो की कर्तव्य-भावना को जगाया है? डर और भय के कारण भले ही उनमें कुछ परिवर्तन हुआ हो, लेकिन सरकार ने उन्हें कर्तव्य का ज्ञान नहीं कराया है। सरकार उन्हें कर्तव्य का ज्ञान अपनी सेवा और अपने चरित्र से ही करा सकती है, तलवार लेकर छाती पर बैठ कर कोई प्रशासक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक पैदा नहीं कर सकता है।

सरकार ने अपनी नीतियों के कारण देश को एक बड़ी भारी विपत्ति में डाल दिया है। उसने अखबारों पर अंकुश लगा दिया है। नागरिकों की जुबान बन्द कर दी है और न्यायालयों का दरवाजा बन्द कर दिया है। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि अगले दस वर्षों का समय देश के लिए भयंकर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार जल्दी से जल्दी प्रजातांत्रिक संस्थाओं और मूल्यों को रेस्टोर करे। आप ने सुना होगा कि भागलपुर जेल में गोली चली है, डैकतियां बंद रही हैं, पटना नगर में बैंक को लूटा गया है। सरकार इस 20-सूत्री कार्यक्रम वा झुनझुना बजा रही है, लेकिन ला एण्ड आर्डर की स्थिति डेटेरियोरट कर रही है।

मैं कहना चाहता हूँ कि 20-सूत्री कार्यक्रम से मुझे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन उसको कार्यान्वित करने के लिए एक प्रजातांत्रिक वातावरण में जनता का सहयोग लेना आवश्यक है।

श्री सरजू पांडे (गाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इस पांच मिनट के समय में मैं केवल कुछ सुझाव ही दूंगा।

लोगो को भारी आशा थी कि इमरजेंसी के बाद जो बजट आएगा वह एक नए प्रकार का बजट होगा, लेकिन जैसा कि मेरी पार्टी के माननीय सदस्यों ने कहा है, यह बजट हिन्दुस्तान के सरमायादारों के हक में है और अभी भी उसमें कोई आमूल परिवर्तन नहीं हुआ है।

जैसा कि सब माननीय सदस्यों ने कहा है, यह बात सही है कि किसानों की पैदावार का दाम गिरा है, मगर दूसरी तरफ उद्योगों में पैदा होने वाले माल का दाम नहीं गिरा है। इससे किसानों की कठिनाइयां और ज्यादा बढ़ी हैं। बहुत जगह बिजली और खाद के दामों में वृद्धि के कारण भी किसानों की परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं। अगर सरकार उद्योग में पैदा होने वाली चीजों के दाम भी गिराये, तो किसानों के माल के दाम गिराने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है।

जहां तक 20-सूत्री कार्यक्रम का संबंध है, यूं तो जब से कांग्रेस ने समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की चर्चा शुरू की है, तब से लगातार कई प्रकार की अच्छी-अच्छी योजनायें बनाई गई हैं, लेकिन उन पर अमल करने की कोई मशीनरी नहीं है। मैं जोधपुर गया था। वहां गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। हर एक आदमी से आल्टरनेटिव जमीन के लिए 500 रुपए की मांग की जा रही है। वे लोग 500 रुपए कैसे दे सकते हैं?

उत्तर प्रदेश के बारे में मैं साफ तौर से कह सकता हूँ कि वहां सारा आवंटन केवल कागजों पर हो रहा है। जो लोग जमीन पर कब्जा किये हुए हैं, उनको बेदखल करने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, और रेडियो पर सुनते हैं कि जमीन का आवंटन हो रहा है। लेकिन इस बारे में जनता का सहयोग नहीं

[श्री सरजू पांडे]

बिना जा रहा है। मुख्य रूप से आर्बिट्रज का सारा काम ब्यूरोक्रेसी के हाथ में दिया गया है। ब्यूरोक्रेसी जैसी हमारे धुन्क की है उनके साथ अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से वह गरीबों को लूटती है। जो 20 सूची कार्यक्रम का लाभ उन्हें होना चाहिए वह नहीं हो रहा है।

12.00 hrs.

दूसरी तरफ हमारे यहां बुनकरी की समस्या है। बीस सूची कार्यक्रम में उनके लिए भी कहा गया है। लेकिन उनकी मांग और खपत का कोई प्रबन्ध अब तक नहीं हो सका है।

मैनेजमेंट में मजदूरों के पार्टिसिपेशन की बात है। उसकी तरफ हमारी पार्टी के लोगों के और लोगों ने भी ध्यान दिलाया है। आज हालत यह है कि सारे देश में साक आउट है। कारखाने बन्द हैं और इस एमर्जेंसी का लाभ उठा कर हिन्दुस्तान के पूंजीपति मजदूरों पर भारी अत्याचार कर रहे हैं। मजदूर बेचारे बोन नहीं सकते हैं। अभी मैं मसौली गया था पीलीभीत जिले में। वहां लोगों को निकाल दिया गया है। कोआपरेटिव की मिल है। वहां का मैनेजमेंट कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। एमर्जेंसी से मजदूरों को जो आशा थी, मजदूर यह समझते थे कि एमर्जेंसी का इस्तेमाल मुनाफाखोरों और बड़े-बड़े बदाभास लोगों के खिलाफ होगा लेकिन वह आज मजदूरों के खिलाफ हो रहा है। इससे मजदूरों में दिनों-दिन असन्तोष बढ़ रहा है।

मैं माननीय सदस्य की इस बात के बहुत ज्यादा तो सहमत नहीं हूँ कि कुछ इस देश में हमारा ही नहीं। मगर मैं यह मानता हूँ कि एमर्जेंसी में अखबार बन्द हैं, जलूस नहीं निकल सकते हैं, सभायें नहीं हो सकती हैं,

उनके खिलाफ कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए पूरी सम्मेलनी पूरे देश में हो रही है। इसको रोकने का कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए।

श्री लक्ष्मि भूषण : आपके अखबार की तो ताबाव बड़ी है।

श्री सरजू पांडे : हमारे अखबार की ताबाव बड़ती है, हमारा अखबार बीड़ा बहुत बिकता है तो उसको नोटिस बिसली है और रोज टेलीफोन किया जाता है।

अब मैं फेमिली प्लानिंग वाले मामले के बारे में कहना चाहता हूँ। बहुत सारे सदस्यों ने यह सवाल उठाया है। यह सरकार कहती है कि हम किसी के साथ जबर्दस्ती नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इसी सदन में माननीय रामानवतार शास्त्री ने पढ़ कर सुनाया कि किस तरह से मर्कुलर भेजे गये हैं और पुलिस को कहा गया है कि हम तुमको दस रुपए दंगे, तां पुलिस वाले ठेले वालों को, इक्के वालों को, टांगे वालों को छोड़े वालों को सबको पकड़-पकड़ कर लाते हैं और अब तां खले आम डाक्टरों को बूस देकर झूठा सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा रहा है। इस फेमिली प्लानिंग से क्या लाभ होगा। मैं खुद एक मोकें पर गया। वहां मैंने देखा कि 60 साधुओं का अपरेशन किया गया था जिनकी उम्र सत्तर साल थी। इस तरह से फेमिली प्लानिंग चलाने से कोई लाभ है? साधु भी, भिक्षुओं भी, पागल भी, कोडी भी, सबको पकड़ पकड़ कर ला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह कहां की बात है?

श्री सरजू पांडे : यह हमारे जिले की बात है जो खुद अपनी आंख से देखा कर आया। उत्तर प्रदेश में कि साधुओं को पकड़ कर

लाया गया, उनको साठ साठ रुपये दिये और उनका आपरेशन किया गया। लोग झूठा सर्टिफिकेट हासिल कर ले रहे हैं . . . (व्यवधान) . . . फ़ेमिली प्लानिंग के बारे में मुझे यह कहना है कि चाहे सरकार ऊपर से भले ही कहती हो कि जबर्दस्ती नहीं करना चाहते हैं मगर इस तरह के निर्देश सरकारी कर्मचारियों को, अध्यापकों को, चक्रवन्दी में काम करने वाले अधिकारियों को और दूसरे लोगों को दिये गये हैं। मैं एक केस को जानता हूँ कि उस आदमी का आपरेशन कराया गया जिसकी शादी हुई ही नहीं थी और यह कहा गया कि तुमको जमीन दी जायेगी। इस लालच में उसका आपरेशन कराया गया। सरकार को इसे देखना चाहिये।

बेकारों की समस्या हमारे देश में बड़ी भारी है। उन बेकारों के लिये प्रोग्राम बनाया गया है कि झाड़ू लगाओ और पेड़ लगाओ। यह योजना कितन दिन चलेगी? यह तो बिल्कुल मुल्क के साथ मजाक हूँ रहा है। जो मुल्क के करोड़ों नौजवान बेकारी से पागल हो कर सारे के सारे जयप्रकाश के मूवमेंट में शामिल हो गये थे, अब वही नौजवान फिर एकट्ठे हुये हैं तो उसको प्रोग्राम दिया गया कि झाड़ू लगाओ, पेड़ लगाओ। तो देश के पड़े लिखे नौजवानों को कैसे समझाया जा सकता है। बेकारी की समस्या को दूर करने के लिये सरकार ने कोई प्रोग्राम देश के सामने नहीं रखा है और यह एक भारी समस्या है। अगर उन बेकारों को काम नहीं दिया गया तो देश में आप चाहे जितनी एमरजन्सी लगा लीजिये कुछ होने वाला नहीं है। एमरजन्सी का प्रभाव अब धीरे धीरे लोगों के दिलों से समाप्त हो रहा है और यह व्यवस्था ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती। या तो आमूल चूल परि-

वर्तन कीजिये। समाज में और कुछ ऐसे कदम उठाइये जिससे बेकारों को काम मिले, गरीबी दूर हो और जो बातें कही गई हैं उनको पूरा किया जाय, अगर वह कदम नहीं उठेगा तो यह झाड़ू लगाने से काम नहीं चलेगा।

एक समस्या की तरफ मैं और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और वह है चीनी मिलों के बारे में। मैं नहीं समझता सरकार के सामने क्या कठिनाई है उनका राष्ट्रीयकरण करने में। लगातार प्रस्ताव पास हुये और हर बार कहा गया कि रात दिन इन चीनी मिलों के द्वारा किसानों की लूट होती है और ये सारे का सारा रुपया सरकार से ले लेते हैं इस नाम पर कि हमारी मिलें खराब हैं, हमारी प्रोडक्शन गिर रही है और किसानों को पैसा नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी इन चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कोई कदम उठाने की बात इस बजट में नहीं कही गई है।

मैं यह मानता हूँ, कि यह ठीक बात है कि देश में कुछ परिवर्तन हुये हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। इस एमरजन्सी से कुछ लाभ हुये हैं। कुछ ऐसे लोगों पर जो देश को गलत दिशा में ले जाना चाहते थे रुकावट आई है। मगर गरीबी अन्याय और लूट जारी है और मैं माननीय सदस्य की इस राय से भी सहमत हूँ कि घूसखोरी बढी है। एक एक सिपाही, एक एक थानेदार इस एमरजन्सी का लाभ उठा कर कितना रुपया कमा रहा है इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हर तरफ से रास्ते बन्द हैं। लोगों में एक घुटन सी पैदा हो रही है। यह घुटन का वातावरण—शशि भूषण जी कहते हैं कि अभी दस साल और बनाये रखा जायें। हम तो कहते हैं दस साल नहीं इसको तो एक दिन में समाप्त किया जा सकता है। लेकिन उस आधार को समाप्त कीजिये जिसकी बदौलत मुल्क में यह स्थिति पैदा हो रही है। मकान

[श्री सरजू पांडे]

गिराये जा रहे हैं, दिल्ली में बुलडोजर चला कर मकान गिराये जा रहे हैं इन नाम पर कि नई बस्तियाँ बसाई जायेंगी। ऐसे ऐसे मकान गिराये जा रहे हैं, एक जगह आप चल कर खुद देख लीजिये, मैं पांडव नगर गया और दूसरी यमुना पार की बस्तियों में गया था . . .

सूच्यल महोदय : आप चीनी मिलों पर समाप्त कर रहे थे, अब बुलडोजर पर आ गये।

श्री सरजू पांडे : मेरा यह निवेदन है कि ये जो मकान गिराये जा रहे हैं इनमें कावट पैदा करनी चाहिये। बिना कालटेर-नेटिव जमीन दिये उनके अच्छे अच्छे मकान गिरा कर दम दम गज जमीन उनको खिचरी-पुर गांव में दी गई है जहाँ बाढ़ में सारे के सारे मकान बह जायेंगे। मेरा निवेदन है कि अगर हम देश को आगे बढ़ाना है तो एमेर्जेन्सी का इस्तेमाल कीजिये उन लोगों के खिलाफ जो देश के शत्रु हैं। मजदूरों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ और आम लोगों के खिलाफ इसका इस्तेमाल होगा तो इसमें जनता में अच्छी भावना नहीं पैदा होगी।

MR. SPEAKER: The hon. Finance Minister. If you like, you can speak sitting.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI C SUBRAMANIAM): Mr Speaker, Sir, after the general budget speech, there was an elaborate discussion on it and I had the privilege of replying to the debate also not only here but also in the other House wherein I had dealt with the various aspects of the economic policy of the Government.

And there had been discussion on the demands of the various Ministries.

There also points have been made and they have been answered. We are in the final stage of the budget of considering and passing the Finance Bill. At this stage, I do not propose again to answer the criticisms or suggestions with regard to general policy. Particularly, the emphasis which has been laid the ideological emphasis which has been laid as usual, by some of the parties, I am not brushing them aside as completely irrelevant but, unfortunately, those ideologies do not fit in with the policies that we have adumbrated for ourselves here which we want to implement. It is in this context that the taxation policy and also the amendments we are making to-day will have to be judged.

In addition to that, my task has been made much easier by the intervention of my colleague, Shri Pranab Kumar Mukherjee, who made a comprehensive speech, particularly, with regard to the taxation administration and some of the other points

So, I propose to confine myself strictly to deal with the contents of the Finance Bill and some of the suggestions that have been made with regard to this Finance Bill and also deal, perhaps again, briefly, with regard to the Government amendments also which we have given for purposes of improving the Finance Bill. This is something like giving the final machining to take out some of the raw edges. The amendments are only on those lines.

I shall first refer to some of the points made with regard to the investment allowance. While Shri H. M. Patel was somewhat surprised that the mining industry was being left out and so also export-oriented industries Shri Salve went so far as to question the very basis on which the industries were included in the Ninth Schedule of the Income-tax Act. Having presumed that the list had no rational basis, he went further to suggest that all industries should get the benefit of

investment allowance. I wish the Government were in a position to sacrifice unlimited revenue. And we will have to cut the plan and investment also to that extent. But, as hon. Members are aware, in order to support the large plan outlay, which we have provided during the year 1976-77 and, at the same time, keep inflationary forces at bay, we have to be highly selective while sacrificing revenue.

The benefits to the economy as a whole have to be carefully weighed before any concession is granted. This is precisely what we have done. Even at the time of drawing up of the list of industries for inclusion in the Ninth Schedule, deep and careful scrutiny was undertaken and only industries which fulfilled the criteria laid down, were included. I would like to recapitulate that the main factors taken into account were:

- (i) the priority of the product from the angle of exports and the essential needs for intermediate and investment goods and essential needs for mass consumption;
- (ii) extent of capacity constraint on production;
- (iii) reasonable expectation of additional capacity creation in response to fiscal incentives; and
- (iv) amenability of the product to precise description.

It was on the basis of the careful application of these criteria that the list of industries to be included in the Ninth Schedule was drawn up. It was not as if the list was prepared in an ad hoc fashion. During the current budget exercise, the list was again reviewed and on the recommendation of the Ministry of Industrial Development, we have added eight more items to the list. I can only assure hon. Members that the matter will be con-

stantly under review and suitable changes will be made to the list from year to year depending on the developing situation.

I was rather surprised to find that while Shri Salve has argued forcefully for the extension of investment allowance which has to be created out of profit, to the backward areas, he had at the same time stated that industries in backward areas cannot expect to make profit for 15 years. Investment allowance is admissible in the case of backward areas also in so far as industries included in the Ninth Schedule are concerned. There are already a package of incentives for industries in backward areas. For instance, Section 80 HH of the Income tax Act exempts 20 per cent of profits derived from industrial undertakings set up in backward areas for a period of 10 years. What is really needed is the selection of appropriate instruments which would give real benefit to the right type of industries coming up in backward areas. Such industries should add to the total wealth of the region rather than deplete it. For the development of backward areas, as I have already mentioned on more than one occasion, the real solution lies in the establishment of industries which exploit the natural resources of the area through a technology appropriate to the manpower resources in the area. Location of large industries might give employment to a limited number of people, but might at the same time also lead to pockets of high purchasing power which ultimately would impoverish the adjoining rural areas. Bihar is a typical example of such a phenomenon. The entire question of development of backward areas is now under examination by a high-powered committee under my esteemed colleague Shri T. A. Pai and I can only assure the hon. Members that whatever fiscal incentives are necessary to really improve conditions in backward areas would be given Government's most considered attention.

[Shri C. Subramaniam]

I shall now clarify certain points in regard to taxation of non-residents for which provision has been made in the Finance Bill. Hitherto, income by way of royalties received by non-residents was charged to tax on a net basis, that is, after allowing deduction in respect of expenses from the gross amount of such income. In the case of foreign companies, the net income received under approved agreements was charged to tax at the rate of 52.5 per cent. Further, lumpsum payments received by non-residents outside India for the delivery of designs and drawings relating to any patent, invention, etc. outside India were not chargeable to tax in India.

Under the Finance Bill, it is proposed to levy income-tax at the rate of 40 per cent on the gross amount of royalties received by foreign companies under approved agreements made on or after 1st April, 1976. Royalties received under approved agreements made before that date will, however, continue to be taxed at the rate of 52.5 per cent on net basis. Further, lumpsum payments received by such companies outside India for the delivery of designs and drawings outside India will be chargeable to tax in India in all cases, irrespective of the date on which the agreement was made. Such lumpsum payments will, however, be charged to tax at the rate of 20 per cent of the gross amount if these are received under approved agreements made on or after the 1st April 1976.

It has been represented that foreign supplies of technical knowhow had entered into agreements or had finalised proposals for the receipt of such lump sum royalties with the approval of the Central Government on the understanding that such payments would be exempted from tax. In order to mitigate hardship in such cases, I proposed to exempt from income-tax the lumpsum payments of this type received under approved agreements

made before 1st April, 1976. Such lumpsum payments received under agreements made after 31st March, 1976, will, at the option of the foreign company, be treated similarly if the agreement was made in accordance with the proposals approved by the Central Government before 1st April, 1976. Foreign companies which exercise an option under the proposed provision will continue to pay income-tax in respect of the remaining royalty income on the existing basis. In other words, income-tax in respect of the remaining royalty income will be charged at the rate of 52.5 per cent on a net basis. The net amount of royalty income will, however, be computed after limiting the deduction on account of expenditure incurred on earning such income to 20 per cent of the gross amount. Foreign companies which do not exercise this option will be governed by the new scheme of taxation of royalties laid down in the Bill. They will, thus, have to pay income-tax at the rate of 20 per cent on the gross amount of the lumpsum royalties and at the rate of 40 per cent on the remaining amount of royalty.

Under another provision in the Finance Bill, interest payable by a non-resident will be deemed to accrue or arise in India if it is payable in respect of any debt incurred or moneys borrowed and used for the purposes of a business or profession carried on by the non-resident in India or for the purposes of making or earning any income from any source in India. It has been represented that while it will be fair to tax interest payable by a non-resident carrying on business in India on moneys borrowed by him from another non-resident for the purposes of his business in India, taxation of interest paid by a non-resident to another non-resident in other cases will result in casting the tax net too wide. Thus, in a case where a non-resident 'A' borrows moneys from another non-resident 'B' for investment in shares of an Indian company, non-resident 'B' should not be charged to

tax on interest received by him from 'A' as the nexus between the investment in India and non-resident 'B' is rather tenuous. It has also been represented that taxation of income in such cases will adversely affect investment in India. I, therefore, propose to exclude from the tax net interest received by a non-resident from another non-resident unless such other non-resident carries on a business or profession in India.

Shri Salve has taken rather strong exception to the fact that outstanding fees in the case of lawyers and solicitors only have been exempted and other professionals have not been covered. Our decision was taken after careful examination of representations received in the matter. We also had before us the considered views of the Attorney General before making the decision. As the House is aware, outstanding fees in the case of pleading advocates and senior advocates who are briefed by junior advocates are not legally recoverable.

SHRI N. K. P. SALVE (Betul): That is wrong, Sir. Every advocate is entitled to sue in the court of law in India.

SHRI C. SUBRAMANIAM: It is difficult, if not impossible, therefore, to ascertain on a fair basis the recoverable outstanding fees of any advocate or solicitor. Besides many advocates act as well as plead in some cases and only plead in certain other cases. Identification of outstanding fees which can be regarded as asset for the purpose of wealth tax would be an insuperable task in these cases. It was on these considerations that exemption has been proposed. The House will appreciate that *prima facie*, these considerations do not apply to the case of those belonging to other professions. However, I have an open mind and if any group of professionals are able to establish that they have a problem similar to, if not identical with that of the category already exempted, I shall respond to their representations. The House will appreciate that in

such cases, snap decisions are just not possible and a careful analysis must precede any decision.

Shri Salve has also urged the removal of the so-called disparity between taxation rates in regard to registered firms, especially of professionals, and individuals. He has at the same time argued equally forcefully for the removal of the disparity of rates applicable to the corporate sector and that applicable to HUFs, individuals and partners. I would like to inform the House that the rates applicable to different tax entities are not determined in an *ad hoc* fashion. They are based on an analytical study of the incidence of taxation with regard to counter-balancing benefits which accrue to the taxable entity. For example, while it is a fact that the combined incidence of income tax on a registered firm and its partners is higher than the tax that would have been paid by the partners of the firm on their respective shares of income if they derived an equal income by separately carrying on their profession or business, this has to be carefully counter-balanced by the special benefits accruing from a partnership as a form of business organisation. In fact, hon. members will recall that the need for a levy of separate tax on registered firms arose as *inter alia* on the consideration that many tax payers found it easy to reduce the tax liability by setting up firms with relatives and friends as partners, some of whom were merely benamidars.

Certain hon. members have, perhaps for ideological reasons, been rather critical of the concessions that have been given in excise duties to the private sector. My colleague, Shri Pranab Mukherjee has already dealt with this in detail. I must, however, say that I am in full agreement with the views of Dr. V. K. R. V. Rao that the ball is now squarely in the court of the private sector and that they should prove equal to the challenge posed to them and the confidence reposed in them by the nation.

[Shri C. Subramaniam]

The tendency to fritter away their energies in a gluttonous mood seeking more and more tax concessions must be discouraged. As I had said during the budget debate, the private sector is on trial. It is for the private sector to prove its worth by its performance.

Certain hon. members pleaded for further relief in respect of excise duty on paper, tractors, certain agricultural implements and bicycles. I have had the matter examined, but I am unable to concede these requests since I find that adequate concessions have already been given in respect of most of these commodities.

Several hon. members have made some constructive suggestions to improve the economy. I can assure them that their suggestions will receive our highest consideration.

I am deeply grateful to hon members for the appreciation they have expressed in regard to the remarkable progress which our economy has registered in recent years. This is indeed a tribute to the inspiring and dynamic leadership of the Prime Minister. Economic progress is closely inter-linked and inter-woven with progress in the political and social spheres of activity. The recent developments in our relations with China and Pakistan are of considerable significance to the future of our country. On the social side, long-standing wasteful and evil practices like dowry etc. are now being speedily eradicated through determined action to arouse the social conscience of the nation. The recently announced population policy is another important step in our relentless drive against poverty. Our achievements in the field of science and technology have already received world-wide acclaim and we are one of the top nations in the world so far as scientific skills and technological talent is concerned. Discipline has been restored in almost every walk of life. Educational insti-

tutions have now become centres of learning once again. Industrial establishments have become places where work is worth doing. Government offices have achieved a level of efficiency never before reached. Shortages of essential commodities is now only an unhappy memory. We have about 13 million tonnes of foodgrains in our godowns today. As you all know, procurement is still going on at a very fast rate.

SHRI BIRHUTI MISHRA (Motihari): But the prices of agricultural commodities have come down and the prices of industrial goods have not gone down proportionately.

SHRI C. SUBRAMANIAM: I have dealt with it in my budget speech. I agree that we should have a balance between agricultural prices and industrial prices. Therefore, there is no question of merely having an Agricultural Prices Commission to fix the price for the benefit of the urban consumer. For other essential commodities, particularly those required by the rural population, we should have commodity councils or price commissions so that the rural population gets the benefits of lesser prices for their consumption goods. This balance will have to be brought out and this balance, I do agree, does not exist today.

Power is no longer a constraint to production. Industrial raw materials are available in abundant measure to keep the wheels of industry moving. Harmonious industrial relations are the order of the day. As was pointed out, we have fertilisers also and there is no shortage of fertiliser today.

Last year, when emergency was declared, the nation was at cross roads. When the new Economic programme was discussed in this august House, I described the situation as a turning point. Yes, indeed, it has been a turning point. We have fully grasped the opportunities thrown up by the new situation brought about by the Emergency. The nation has enter-

of a new era of progress and social regeneration. It, therefore, behoves each one of us to do our mite to consolidate the gains of emergency, ensure that the momentum generated is sustained, if not strengthened, that the qualitative change in all facets of national life is preserved if not improved, and strive our utmost for the speedy attainment of our cherished goals of a better standard of living for our millions and better quality of life especially in rural India.

Sir, I move.

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 1976-77, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: Now, we take up clause by clause discussion. Since there are no amendments to clauses 2 and 3, I will put them to the vote of the House.

MR. SPEAKER: The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 4 (Amendment of section 9)

MR. SPEAKER: Now, we take up clause 4. There are four Government amendments.

Amendments made:*

Page 7, lines 35 and 36, omit

"or for the purposes of making or earning any income from any source in India". (89).

Page 8, after line 13, insert—

"Provided that nothing contained in this clause shall apply in relation to so much of the income by way of royalty as consists of lump sum

consideration for the transfer outside India of, or the imparting of information outside India in respect of, any data, documentation, drawing or specification relating to any patent, invention, model, design, secret formula or process or trade mark or similar property, if such income is payable in pursuance of an agreement made before the 1st day of April, 1976 and the agreement is approved by the Central Government.

Explanation 1 For the purposes of the foregoing proviso, an agreement made on or after the 1st day of April, 1976 shall be deemed to have been made before that date if the agreement is made in accordance with proposals approved by the Central Government before that date; so, however, that, where the recipient of the income by way of royalty is a foreign company, the agreement shall not be deemed to have been made before that date unless, before the expiry of the time allowed under sub-section (1) or sub-section (2) of section 139 (whether fixed originally or on extension) for furnishing the return of income for the assessment year commencing on the 1st day of April, 1977, or the assessment year in respect of which such income first becomes chargeable to tax under this Act, whichever assessment year is later, the company exercise an option by furnishing a declaration in writing to the Income-tax Officer (such option being final for that assessment year and for every subsequent assessment year) that the agreement may be regarded as an agreement made before the 1st day of April, 1976." (90).

Page 8, line 14, for "Explanation", substitute "Explanation 2". (91)

Page 9, line 23, for "assembly or",

Substitute "assembly, mining or". (92).

(Shri C Subramaniam).

*Moved with the recommendation of the President.

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 4, as amended, stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 4, as amended, was added to the Bill.

Clause 5 (Amendment of Section 10)

MR. SPEAKER: Now, clause 5. There is a motion for suspension of Rule 80(i).

SHRI C. SUBRAMANIAM: I beg to move:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No. 93 to the Finance Bill, 1976 and that this amendment may be allowed to be moved." (109)

MR. SPEAKER: The question is:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No. 93 to the Finance Bill, 1976 and that this amendment may be allowed to be moved." (109)

The motion was adopted

Amendment made:

Page 10, after line 29, insert—

'(c) in clause (17), for the words "any Committee thereof," the words, brackets and figures "any Committee thereof or any allowance received by a member of

either House of Parliament under the Members of Parliament (Additional Facilities) Rules, 1976," shall be substituted.' (98)

(Shri C. Subramaniam)

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 5, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 5, as amended, was added to the Bill.

MR. SPEAKER: There are no amendments to Clauses 6 and 7. I put them to the vote of the House together.

The question is:

"That clauses 6 and 7 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 6 and 7 were added to the Bill.

MR. SPEAKER: Regarding clause 8, there is one amendment in the names of Mr. Somnath Chatterjee and Mr. Dinen Bhattacharya. They are not here. There is no amendment to Clause 9. I put clauses 8 and 9 together

The question is:

"That clauses 8 and 9 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 8 and 9 were added to the Bill.

Clause 10 (Insertion of new sections 44C and 44D)

*Moved with the recommendation of the President.

MR. SPEAKER: Now Clause 10.
SHRI C. SUBRAMANIAM. I move amendments Nos. 94, 95, 96 and 97.

I beg to move*:

Page 19, lines 6 and 7, for "referred to in sub-section (2) of section 32", substitute "referred to in this section or in sub-section (2) of section 32." (94)

Page 19, line 13, for "deduction", substitute "deductions". (95)

Page 20, for line 36, substitute—

"gross amount of such royalty or fees as reduced by so much of the gross amount of such royalty as consists of lump sum consideration for the transfer outside India of, or the imparting of information outside India in respect of, any data, documentation, drawing or specification relating to any patent, invention, model, design, secret formula or process or trade mark or similar property;" (96)

Page 21, after line 11, insert—

"(d) royalty received from an Indian concern in pursuance of an agreement made by a foreign company with the Indian concern after the 31st day of March, 1976 shall be deemed to have been received in pursuance of an agreement made before the 1st day of April, 1976 if such agreement is deemed, for the purposes of the proviso to clause (vi) of sub-section (1) of section 9, to have been made before the 1st day of April, 1976;" (97)

MR. SPEAKER: The question is:

Page 19, lines 6 and 7, for "referred to in sub-section (2) of section 32", substitute "referred to in this section or in sub-section (2) of section 32". (94)

Page 19, line 13, for "deduction", substitute "deductions". (95)

Page 20, for line 36, substitute—

"gross amount of such royalty or fees as reduced by so much of the gross amount of such royalty as consists of lump sum consideration for the transfer outside India of, or the imparting of information outside India in respect of, any data, documentation, drawing or specification relating to any patent, invention, model, design, secret formula or process or trade mark or similar property;" (96)

Page 21, after line 11, insert—

"(d) royalty received from an Indian concern in pursuance of an agreement made by a foreign company with the Indian concern after the 31st day of March, 1976 shall be deemed to have been received in pursuance of an agreement made before the 1st day of April, 1976 if such agreement is deemed, for the purposes of the proviso to clause (vi) of sub-section (1) of section 9, to have been made before the last day of April, 1976" (97)

The motion was adopted

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 10, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 10, as amended, was added to the Bill.

MR. SPEAKER: There are no amendments in regard to clauses 11 to 16 I put them together. The question is:

"That clauses 11 to 16 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 11 to 16 were added to the Bill.

Clause 17 (Amendment of section 80G).

*Moved with the recommendation of the President.

[Shri C. Subramaniam]

MR. SPEAKER: Now clause 17. There are government amendments. There is also a motion for suspension of rule 80 (d).

SHRI C. SUBRAMANIAM: I beg to move:

"That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No. 98 to the Finance Bill, 1976 and that this amendment may be allowed to be moved." (110)

MR. SPEAKER: The question is: "That this House do suspend clause (i) of rule 80 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to Government amendment No. 98 to the Finance Bill, 1976 and that this amendment may be allowed to be moved." (110)

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: Now the Minister. SHRI C. SUBRAMANIAM: I beg to move*:

Page 22, for lines 26 to 33, substitute—

'(a) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted with effect from the 1st day of April, 1977, namely:—

"(1) In computing the total income of an assessee, there shall be deducted, in accordance with and subject to the provisions of this section,—

(i) in a case where the aggregate of the sums specified in

sub-section (2), includes any sum specified in sub-clause (vii) of clause (a) thereof, an amount equal to the whole of such sum plus fifty per cent. of the balance of such aggregate; and

(ii) in any other case, an amount equal to fifty per cent. of the aggregate of the sums specified in sub-section (2).";

(b) in clause (a) of sub-section (2), with effect from the 1st day of April, 1977,—

(i) in sub-clause (v), for the words "for any charitable purpose";, the words "for any charitable purpose other than the purpose of promoting family planning; or" shall be substituted;

(ii) after sub-clause (v), the following sub-clauses shall be inserted, namely —

"(vi) any authority referred to in clause (20A) of section 10; or

(vii) the Government to any such local authority, institution or association as may be approved in this behalf by the Central Government, to be utilised for the purpose of promoting family planning."; (98)

Page 22, line 34, for "(b)", substitute "(c)" (99)

Page 22, for line 36, substitute— 'and figures "sub-clauses (iv), (v), (vi) and (vii)" shall be. 100)

Page 23, line 1, for "(c)", substitute "(d)". (101)

MR. SPEAKER: The question is:

Page 22, for lines 26 to 33, substitute—

'(a) for sub-section (1), the following sub-section shall be

substituted with effect from the 1st day of April, 1977, namely:—

“(1) In computing the total income of an assessee, there shall be deducted, in accordance with and subject to the provisions of this section,—

(i) in a case where the aggregate of the sums specified in sub-section (2) includes any sum specified in sub-clause (vii) of clause (a) thereof, an amount equal to the whole of such sum plus fifty per cent. of the balance of such aggregate; and

(ii) in any other case, an amount equal to fifty per cent. of the aggregate of the sums specified in sub-section (2).”;

(b) in clause (a) of sub-section (2), with effect from the 1st day of April, 1977,—

(i) in sub-clause (v), for the words “for any charitable purpose;”, the words “for any charitable purpose other than the purpose of promoting family planning; or” shall be substituted;

(ii) after sub-clause (v), the following sub-clauses shall be inserted, namely:—

“(vi) any authority referred to in clause (20A) of section 10; or

(vii) the Government or to any such local authority, institution or association as may be approved in this behalf by the Central Government, to be utilised for the purpose of promoting family planning;”’. (98)

Page 22, line 34, for “(b)”, substitute “(c)”. (99)

Page 22, for line 35, substitute—

‘and figures “sub-clauses (iv), (v), (vi) and (vii)” shall be.’ (100)

Page 23, line 1, for “(c)”, substitute “(d)”. (101)

MR. SPEAKER: The question is:

Page 22, for lines 26 to 33, substitute—

‘(a) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted with effect from the 1st day of April, 1977, namely:—

“(1) In computing the total income of an assessee, there shall be deducted, in accordance with and subject to the provisions of this section,—

(i) in a case where the aggregate of the sums specified in sub-section (2) includes any sum specified in sub-clause (vii) of clause (a) thereof, an amount equal to the whole of such sum plus fifty per cent. of the balance of such aggregate; and

(ii) in any other case, an amount equal to fifty per cent. of the aggregate of the sums specified in sub-section (2).”;

(b) in clause (a) of sub-section (2), with effect from the 1st day of April, 1977,—

(i) in sub-clause (v), for the words “for any charitable purpose;” the words “for any charitable purpose other than the purpose of promoting family planning; or” shall be substituted;

(ii) after sub-clause (v), the following sub-clauses shall be inserted, namely:—

“(vi) any authority referred to in clause (20A) of section 10. or

(vii) the Government or to any such local authority, institution or association as may be approved in this behalf by the Central Government, to be utilised for the purpose of promoting family planning;”’. (98)

Page 22, line 34 for “(b)”, substitute “(c)”. (99)

*Moved with the recommendation of the President.

[Mr. Speaker]

Page 22, for line 36, substitute—

'and figures "sub-clauses (iv), (v), (vi) and (vii)" shall be', (100)

Page 23, line 1, for "(c)", substitute "(d)". (101)

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 17, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 17, as amended, was added to the Bill.

Clause 18 (Amendment of section 80M).

MR. SPEAKER: Now, there is a government amendment for clause 18.

Amendment* made:

Page 23, for lines 26 to 29, substitute—

"specified in items 2 and 3, item 4 (excluding alloy, malleable and S. G. iron castings), items 7 to 15 (both inclusive), items 17 and 18, item 23 (excluding refractories) and items 24, 26, 27 and 29 in the list in the Ninth Schedule". (102)

(SHRI C Subramaniam)

MR. SPEAKER: The question is

"That clause 18, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 18, as amended, was added to the Bill.

MR. SPEAKER. There is no amendment to clause 19. The question is:

"That clause 19 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 19 was added to the Bill.

Clause 20 (Insertion of new sections 115A and 115B).

MR. SPEAKER: There are government amendments in clause 20.

Amendment* made:

Page 24, line 4, for "115A. Where", substitute "115A. (1) Subject to the provision of sub-section (2), where". (103)

Page 25, after line 9, insert—

"(2) Nothing contained in sub-section (1) shall apply in relation to any income by way of royalty received by a foreign company from an Indian concern in pursuance of an agreement made by it with the Indian concern after the 31st day of March, 1976 if such agreement is deemed, for the purposes of the proviso to clause (vi) of sub-section (1) of section 9, to have been made before the 1st day of April, 1976; and the provisions of the annual Finance Act for calculating, charging, deducting or computing income-tax shall apply in relation to such income as if such income had been received in pursuance of an agreement made before the 1st day of April, 1976". (104)

(Shri C. Subramaniam)

MR. SPEAKER. The question is:

"That clause 20, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 20 was added to the Bill.

MR. SPEAKER. There are no amendments to clauses 21 to 24. I put them to the vote of the House. The question is:

"That clauses 21 to 24 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 21 to 24 were added to the Bill.

Clause 25 (Amendment of Ninth Schedule).

*Moved with the recommendation of the President.

Amendment* made:

Page 27, for lines 31 to 33, substitute—

'Amendment of Ninth Schedule.

25. In the Ninth Schedule to the Income-tax Act,—

(a) for item 4, the following item shall be substituted, namely:—

"4. Steel castings and forgings and alloy, malleable and S. G. iron castings.";

(b) after item 24 and before the Explanation, the following items shall be inserted, namely:—'. (105)

(Shri C. Subramaniam)

MR. SPEAKER: The question is "That clause 25, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 25, as amended, was added to the Bill.

Clause 26 was added to the Bill.

Clause 27 (Amendment of Act 27 of 1957)

SHRI DINEN BHATTACHARYA: I beg to move:*

Page 33, line 25,—

for " $\frac{1}{2}$ " substitute " $\frac{3}{4}$ " (2)

Page 33, line 28,—

for " $\frac{1}{2}$ " substitute "2" (3)

Page 33, line 32,—

for "2" substitute "3" (4)

Page 33, line 36,—

for " $\frac{2}{3}$ " substitute "5" (5)

Page 34,—

Omit lines 4 to 6 (6)

Page 34,—

Omit lines 24 to 26 (7)

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: I beg to move*:

Page 33, line 25,—

for " $\frac{1}{2}$ " substitute "1" (28)

Page 33, line 28,—

for " $\frac{1}{2}$ " substitute " $\frac{2}{3}$ " (29)

Page 33, line 32,—

for "2" substitute " $\frac{3}{4}$ " (30)

Page 33, line 36,—

for " $\frac{2}{3}$ " substitute "6" (31)

Page 33, line 28,—

for "Rs. 2,500 plus $\frac{1}{2}$ per cent" substitute "Rs. 5,000 plus 3 per cent." (53)

Page 33, line 32,—

for "Rs. 19,000 plus 2 per cent." substitute—

"Rs. 20,000 plus 1 per cent." (54)

Page 33, line 36,—

for "Rs. 20,000 plus $\frac{2}{3}$ per cent."

substitute "Rs. 40,000 plus 5 per cent." (55)

Page 34, line 3,—

for "Rs 1,00,000 substitute "Rs. 50,000" (56)

Page 34, line 11,—

for " $\frac{1}{2}$ per cent" substitute "3 per cent." (57)

Page 34, line 14,—

for "Rs. 7,500 plus 2 per cent." substitute "Rs. 15,000 plus 4 per cent." (58)

Page 34, line 18,—

for "Rs 17,500 plus $\frac{2}{3}$ per cent." substitute—

"Rs. 35,000 plus 5 per cent." (59)

Page 34, line 23,—

for "Rs 1,00,000", substitute "Rs. 50,000" (60)

SHRI C SUBRAMANIAM: I beg to move*.

Page 32, in line 26, for "shall", substitute "may, at the option of the assessee,". (106)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, पेज 33 और 34 में जहाँ वैल्यू टैक्स की बात कही गई है, वहाँ हमारे कई मंशोधन हैं। सरकार जो अभी उन पर कर लगाने की कोशिश कर रही है, वह बहुत ही कम है क्योंकि उनके पास पैसा बेकार पड़ा हुआ है। अगर सरकार को यह उम्मीद हो कि वे नोग अपनी विशाल धनराशि को किसी कारखाने या किसी उद्योग में लगायेंगे, तब तो ठीक है लेकिन हमारा यह खयाल है कि वे बड़े बड़े धनपति हैं, उनके पास ज्यादा धन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे उस धन को इसरी तरह वे कामों में लगायेंगे जिसमें देश की तरक्की नहीं होगी। वे अपने

*Moved with the recommendation of the President.

[श्री राधाकृष्णन की ओर से]

रुपये-पैसे को उद्योग-धन्धों में बिक्री से नहीं खपाना चाहेंगे। इसलिये इस बात को ध्यान से रखते हुये हमें खनकी सम्पत्ति पर ज्यादा से ज्यादा कर लगाने चाहिये ताकि उनके पास पैसा बेकार न पडा रहे, जिसका इस्तेमाल कर के वे खोखली करे या गलत तरीके के धन्धो में लगाये। इसीलिये मैं अपने सभाधन के जरिये से यह चाहता हूँ कि जहा इस बात की चर्चा है कि पांच लाख रुपये तक धाधा परसेन्ट टैक्स प्राप लगाना चाहते हैं, उसको धाधा परसेन्ट से बढ़ा कर एक परसेन्ट कर दिया जाये ताकि उन ५ लाख से कुछ पैसा निकले और सरकारी खजाने से धार्ये।

फिर उन्होंने कहा है कि कहा 5 लाख से ज्यादा और 10 लाख रुपये तक है वहा,, इन्होंने टैक्स लगाने की कॉमिग की है 25 00 रुपये और उसके धलावा डेड प्रतिशत के हिसाब से। मेरा अनुरोध यह है कि 2,5 00 रुपये को 5,000 रुपये कर दिया जाये और डेड प्रतिशत को बढ़ा कर तीन प्रतिशत कर दिया जाये ताकि जिन ५ लाख से दस लाख रुपये तक को सम्पत्ति है, उनसे हम ज्यादा टैक्स ले सकें और उद्योग-धन्धो और विकास के कामो मे लगा सकें, जिसेसे देश की तरक्की हो।

उसी तरह से जहा इन्होंने दस लाख से पन्द्रह लाख सम्पत्ति रखने वाली पर दस हजार रुपये और दो प्रतिशत कर लगाने को कॉमिग की वहा हमारा कहना है कि यह बौस और चार प्रतिशत यामी दुगुना होना चाहिये। जहा इन्होंने पन्द्रह लाख पर बीस हजार और ढाई परसेन्ट लगाने की बात कही है वहा हमारा कहना यह है कि इसको चालीस हजार और पांच परसेन्ट कर दिया जाये। इस तरह से हमने ब्रेड्स को बढ़ाने के लिये कहा है। ऐसा हमने इसलिये कहा है ताकि हम उनसे पैसा ले सकें।

भाषने पृष्ठ 24 में कही है

"(i) no wealth-tax shall be payable where the net wealth does not exceed Rs. 1,00,000;"

इसको ये मुक्त रखना चाहते हैं। हमने कहा है कि एक लाख की सीमा की बटा कर पचास हजार कर दिया जाना चाहिये।

उसी तरह से लाइज चार, पांच और छ में धापने कहा है :

"(ii) the wealth-tax payable shall, in no case, exceed 5 per cent of the amount by which the net wealth exceeds Rs. 1,00,000."

इसको हम हटा देना चाहते हैं। पांच परसेन्ट की सीमा लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से लाइज 24, 75 और 26 में भी इसी तरह की बात कही गई है, इसको भी हम चाहते हैं कि हटा दिया जाये।

ये सब सम्पत्ति कर से सम्बन्धित मेरे सभाधन हैं। मैं आशा करता हूँ कि सत्री महोदय इनको स्वीकार कर लेंगे। जिनके पास फालतू धार बेकार धन पडा हुआ है, सम्पत्ति पडी हुई है उनसे ज्यादा से ज्यादा पैसा ले कर हमको उस पैसे का उत्पादक कार्यों मे, उद्योग धन्धो को बढ़ाने मे लगाना चाहिये। जब कि हमारे पास पैसे की कमी है, दूसरो पर टैक्स लगा कर हम पैसा लेना चाहते हैं वहा हमको यह देखना चाहिये कि जिनके पास ज्यादा पैसा जमा है, वह बेकार पडा हुआ है, सम्पत्ति जमा है, उन पर ज्यादा टैक्स न लगाना उचित मान्य नहीं पडता है उन पर अधिक से अधिक कर लगाना चाहिये और छोटों को छूट देनी चाहिये। इन छोटो के सिवसिसे हम बाद मे बात करेगे।

SHRI N. K. P. SALVE: Sir, in view of the assurance of the Finance Minister that he will examine the position afresh of all the proposals in respect of outstanding bills, I do not move the amendments.

MR. C. SUBRAMANIAM: I am not able to accept any of the amendments moved by Shri Ram Avtar Shastri.

MR. SPEAKER: First I put amendment Nos. 2 to 7 moved by Shri Dinan Bhattacharyya to the vote of the House.

Amendments Nos. 2 to 7 were put and negatived.

MR. SPEAKER: Then I put amendment Nos. 28 to 31 and 53 to 60 moved by Shri Ram Avtar Shastri to the vote of the House.

Amendments Nos. 28 to 31 and 53 to 60 were put and negatived.

MR. SPEAKER: Now, I put the Government amendment No. 106 to the vote of the House.

The question is:

Page 32, in line 26, for "shall", substitute "may, at the option of the assessee."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: The question is:

"That Clause 27, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 27, as amended, was added to the Bill.

Clauses 28 to 31 were added to the Bill.

Clause 32 (Auxiliary duties of Customs)

Amendment made:

Page 38,—

after line 7, insert—

'Provided that on and from the date on which the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) comes into force, this sub-section shall have effect subject to the modification that for the words "First Schedule to the Tariff Act", the words and figures "First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975" (51 of 1975); shall be substituted. (88).

(Shri C. Subramaniam;

MR. SPEAKER: The question is: "That clause 32, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 32, as amended, was added to the Bill.

Clauses 33 to 43 were added to the Bill.

First Schedule

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: I beg to move*:

Page 55, line 30,—

for "8,000" substitute "10,000" (8)

Page 55, line 32,—

for "8,000" substitute "10,300" (9)

Page 55, line 33,—

for "8,000" substitute "10,000" (10)

Page 56, line 13,—

for "60" substitute "65". (11)

DR. RANEN SEN: I beg to move*:

Page 45, line 15,—

for "Rs. 8,000" substitute Rs. 12,000" (61)

Page 45, line 16,—

for "17 per cent" substitute "3 per cent." (62)

Page 45, line 17,—

for "Rs. 8,000" substitute "Rs. 12,000" (63)

Page 45, line 18,—

for "Rs. 8,000 substitute "Rs. 12,000" (64)

Page 45, line 19,—

for "Rs. 1,190 plus 20 per cent." substitute—

"Rs. 390 plus 9 per cent." (65)

Page 45, line 22,—

for "Rs. 2,190 plus 30 per cent substitute—

"Rs. 1,190 plus 20 per cent." (66)

Page 45, line 31,—

for "60 per cent." substitute "65 per cent." (67)

Page 45, line 34,—

for "70 per cent." substitute "75 per cent." (68)

*Moved with the recommendation of the President.

[Dr. Ranen Sen]

Page 46, line 13.—

for "Rs. 8000" substitute "Rs. 12,000" (69)

Page 46, line 14.—

for "20 per cent." substitute "5 per cent." (70)

Page 46, line 16.—

for "Rs. 8,000" substitute "Rs. 12,000" (71)

Page 46, line 17.—

for "Rs. 1,400 plus 30 per cent" substitute—

"Rs. 300 plus 10 per cent." (72)

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: The exemption limit has been fixed at Rs. 8,000/-. My amendment is that, in place of Rs. 8,000/- it should be Rs. 10,000/-. This is because the Government has amended the categorisation of workers so far as wages are concerned. Previously, a man drawing up to Rs. 500 was being treated as a workman but now this has been raised to Rs. 1,000/-. So, in that context, this limit of Rs. 8,000 has no meaning; it must be Rs. 10,000/-. Actually, what is the value of Rs. 10,000/- nowadays? When I came to the Lok Sabha for the first time (at that time Mr. Salve was not there) the limit was Rs. 3,500/-. But, today, even if I get Rs. 8,000 the value does not come to Rs. 3,500/-. So I plead with the Minister to kindly consider this and raise the limit from Rs. 8,000/- Rs. 10,000/- so that the poorer strata of workers and employees may be relieved to some extent.

The other amendments are only consequential.

DR. RANEN SEN: My amendment is that, instead of Rs. 8,000/- as the exemption limit, it should be Rs. 12,000/-. There has been amendment of the Industrial Disputes Act by which the definition of a workman has been changed to apply to people who are drawing up to Rs. 750/- per month—which comes to above Rs. 8,000/-. So,

these workers will be involved in this scale of income-tax. Secondly, there has recently been a change in the Employees State Insurance Scheme. An amending Bill was passed here by which even workers getting Rs. 1,000/- per month have been included in the Employees State Insurance Act.

By an amendment, very recently, it has been done. I plead that, instead of Rs. 8,000, it should be Rs. 12,000, because of these two amending Acts that have been passed by this House—one, very recently.

In the scheme of rates of income-tax, I find that people in the higher slabs have got more concessions than the people in the slab above Rs. 8,000. This is not proper keeping in view the sense of natural justice. Therefore, we had made some calculations, and I have moved the amendments accordingly.

SHRI C. SUBRAMANIAM: I am sorry I am unable to accept these amendments. As a matter of fact, these were mentioned during the general debate, and I have answered why it is not possible at this stage. Perhaps, in the next Budget, these may be taken into consideration.

MR. SPEAKER: I shall now put Amendments Nos. 8, 9, 10 and 11, moved by Shri Dinen Bhattacharyya, to the vote of the House.

Amendments Nos. 8 to 11 were put and negatived.

MR. SPEAKER: I shall now put Amendments Nos. 61 to 72, moved by Dr. Ranen Sen, to the vote of the House.

Amendments Nos. 61 to 72 were put and negatived.

MR. SPEAKER: The question is: "That the First Schedule stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The First Schedule was added to the Bill.

The Second and Third Schedules were added to the Bill.

Fourth Schedule

SHRI DINEN BHATTACHARYYA:
I beg to move*:

Page 73, line 31,—

for "twenty-five" substitute "ten"
(12)

Page 73, line 34,—

for "Thirty" substitute "Fifteen"
(13)

Page 74, line 17,—

for "Three" substitute "Two" (14)

Page 74, line 21,—

for "Three" substitute "One" (15)

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: I
beg to move*:

Page 73, line 31,—

for "Twenty-five" substitute "Fifteen"
(36)

Page 73, line 34,—

for "Thirty" substitute "Twenty"
(37)

Page 74, line 21,—

for "Three" substitute "one and a half"
(39)

SHRI DINEN BHATTACHARYYA:
My amendments are very simple. Amendments Nos. 12 and 13 are on page 73. Here in the Bill it is mentioned "Uncoated and coated printing and writing paper (other than poster paper) — Twenty-five per cent *ad valorem*" and for the next one, it is thirty per cent *ad valorem*. In the place of "twenty-five" and "thirty" I have suggested "ten" and "fifteen" respectively because it is the common people who are using these papers and paper board; therefore, my Amendments Nos. 12 and 13 are for reducing the *ad valorem* duty to "ten" and "fifteen" per cent.

My Amendment No. 14 is on page 74, line 17. Here in the Bill it is mentioned:

"Cotton fabrics, medium E, that is to say, fabrics in which the average count of yarn is 17s or more but is less than 26s—Three per cent *ad valorem*"

My amendment is that, instead of three per cent, it must be two per cent. It will give some relief to the consumers who are mostly poor, who belong to low and middle income groups.

My Amendment No. 15 is on page 74, line 21. In the Bill it is mentioned:

"Cotton fabrics, coarse—that is to say, fabrics in which the average count of yarn is less than 17s—Three per cent *ad valorem*"

Here my amendment is that, instead of three per cent, it should be one per cent, because, this coarse cloth is used by the common people.

So, some concession must be given in this case and instead of three per cent, the excise duty should be made two per cent. Another amendment that I have moved is of the same nature. In line 21, I have moved that instead of three per cent, the excise duty should be changed to two per cent. This is because the rate of duty that has been proposed in the Bill will go to increase the burden on the common people. I have suggested this to reduce that burden. These are very important matters and the Government always professes that they will look after the condition of the poor and the poverty-stricken people, but here the way the excise duty is proposed to be levied, it is seen that in the case of the affluent section of people, the charge would be less in proportion to that charged from the poor and the common people. If the Government is true to their profession, they must see the justification in my amendments and accept these.

*Moved with the recommendation of the President.

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरे पहले दो संशोधन तो कागज से संबंध रखने वाले हैं। मंत्री जी ने कहा कि कागज पर से कर और कम वह नहीं करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि कागज हमारे देश में गरीब से गरीब जनता इस्तेमाल में लाती है, वह शहर की हो या देहात की हो। इस बात को ध्यान में रख कर भी अगर सरकार उन पर ज्यादा टैक्स लगाती है तो यह मैं समझता हूँ उचित नहीं है, अनुचित है। इस के उपयोग को देखते हुए और ज्यादा से ज्यादा जनता जो इस का इस्तेमाल करती है इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें इसे और कम करना चाहिए। इसीलिए मैंने यह दिया है कि 25 प्रतिशत ऐड-बेलोरम की बात जो कही गई है उसको 15 प्रतिशत किया जाए और जहां 30 प्रतिशत की बात कही है उसको 20 प्रतिशत किया जाय ताकि आम लोगों को कुछ राहत मिल सके। आम लोगों की बात तो हम सभी बहुत करते हैं। लेकिन टैक्स लगाने की बात आती है तो उन पर लगा देते हैं।

दूसरे संशोधन कपड़े के मंत्र में हैं। कपड़ा हर आदमी इस्तेमाल करता है और उस में गरीब ज्यादा हैं। कपड़े पर ज्यादा टैक्स लगा देंगे तो जाहिर बात है कि गरीबों को ज्यादा दाम देना पड़ेगा और गरीबों की हालत क्या है? वे लोग जो पदयात्रा में गए होंगे या जो पदयात्रा से पहले और बाद में भी गांवों में जाते रहते हैं उन को मालूम है कि कितने ही लोगों को कपड़े मिलते ही नहीं हैं। जाड़ों में भी उन के बदन पर कपड़े नहीं होते, गर्मी में तो कपड़े होने का सवाल ही नहीं। तो जहां 3 परसेंट की बात कही गई है वहां उसे एक परसेंट कम कीजिए, 2 परसेंट कर दीजिए और जहां काटन फ़ैब्रिक्स के ऊपर 3 परसेंट की बात कही है, वहां उसको डेढ़ परसेंट कर दीजिए। यही मेरे संशोधनों का आशय है, कागज पर और कपड़े पर टैक्स कम किया जाये ताकि आम

जनता इस कर भार से मुक्त रह सके, उस को कुछ सहूलियत मिले, राहत मिले।

SHRI C. SUBRAMANIAM: I am sorry. I am unable to accept these amendments. As a matter of fact, we have considered the question of paper and we gave some concession about which notification has already been issued. Even with regard to the processed fabrics produced by power-looms, we wanted to give some concessions and that has also been done by notification. I am sorry. I am unable to accept any of these amendments.

MR. SPEAKER: I will now put amendments Nos. 12 to 15 moved by Shri Dinan Bhattacharyya to vote.

Amendments Nos. 12 to 15 were put and negatived.

MR. SPEAKER: I will now put the amendments of Shri Ramavatar Shastri to vote.

Amendments Nos. 36, 37 and 39 were put and negatived.

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Fourth Schedule stand part of the Bill".

The motion was adopted.

The Fourth Schedule was added to the Bill.

The Fifth Schedule was added to the Bill.

Sixth Schedule

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: I beg to move*:

Page 77, line 13,—

for "Twenty" substitute "Ten" (16)

Page 77, lines 14 and 15,—

for "rupees three and seventy-five" substitute "rupee one and seventy-five" (17)

*Moved with the recommendation of the President

- Page 77, lines 20 and 21,—
for "Rupees three and seventy-five" substitute "Rupee one and fifty" (18)
- Page 77, line 29,—
for "Twenty" substitute "Ten" (19)
- Page 77, line 31,—
for "seven" substitute "three" (20)
- Page 78, line 2,—
for "thirty" substitute "fifteen" (21)
- Page 78, line 6,—
for "Twenty" substitute "Ten" (22)
- Page 78, line 22,—
for "thirty" substitute "fifteen" (23)
- Page 78, line 27 —
for "Twenty" substitute "ten" (24).
- Page 78, line 31,—
for "seven" substitute "three" (25)
- Page 79, line 3,—
for "Sixty" substitute "Thirty" (26)
- Page 79, line 5,—
for "seven" substitute "three" (27)
- SHRI RAMAVATAR SHASTRI: I beg to move*:
- Page 77, line 13,—
for "Twenty" substitute "Twelve" (40)
- Page 77, lines 15 and 16,—
for "three and seventy-five paise" substitute "two" (41)
- Page 77, lines 20 and 21,—
for "three and seventy-five paise" substitute "two" (42)
- Page 77, line 29,—
for "Twenty" substitute—
"Twelve" (43)
- Page 77, lines 31 and 32,—
for "seven and fifty paise" substitute "four" (44)
- Page 78, line 2,—
for "thirty" substitute "twenty" (45)
- Page 78, line 6,—
for "Twenty" substitute "Twelve" (46)
- Page 78, line 22,—
for "thirty" substitute "twenty" (47)
- Page 78, line 27,—
for "Twenty" substitute "Twelve" (48)
- Page 78, lines 31 and 32,—
for "seven and fifty paise" substitute—
"four" (49)
- Page 79, line 3,—
for "Sixty" substitute "Forty" (50)
- Page 79, lines 5 and 6.—
for "seven and fifty paise" substitute—
"four" (51)

*Moved with the recommendation of the President.

[Shri Ranavvatar (Shastri)]

Page 77, lines 13 to 19,—

for "Twenty per cent. *ad valorem* or rupees three and seventy-five paise per litre of the strength of London proof spirit, whichever is higher."

substitute—

"Nil." (82)

DR. RANEN SEN. I beg to move*:

Page 77, lines 13 to 16,—

for "Twenty per cent. *ad valorem* or rupees three and seventy-five paise"

substitute—

"One per cent *ad valorem* or thirty-five paise" (73)

Page 77, lines 20 and 21,—

for "Rupees three and seventy-five paise"

substitute "Thirty-seven paise" (74)

Page 77, lines 29 to 32,—

for "Twenty per cent *ad valorem* or rupees seven and fifty paise"

substitute "One per cent *ad valorem* or thirty-five paise" (75)

Page 78, line 2,—

for "Rupees thirty" substitute

"Rupees two" (76)

Page 78, line 6,—

for "Twenty" substitute "two" (77)

Page 78, line 17,—

for "Rupee one" substitute "Five paise" (78)

Page 78, line 22,—

for "Rupees thirty" substitute

"Rupees three" (71)

Page 78, line 27,—

for "Twenty" substitute "One" (80)

Page 78, lines 31 and 32,—

for "Rupees seven and fifty paise" substitute "Ten paise" (81)

13.56 hrs.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA:

I would request the Minister to consider that for medical preparations a certain amount of alcohol is necessary on which he has raised the duty which will seriously affect the people who come from the middle strata and the lower strata. There, I have suggested that at least he must be considerate enough to reduce the rates and there is nothing much to speak on it. It has to be realised by the Finance Minister that it will ultimately affect the ordinary people of our country and if these rates are reduced, the benefit will go to the common people and considering all these aspects, I think he will kindly accept my amendment, specially in regard to those items where alcohol will be required. Even for homoeopathic medicines you will find that he has levied an excise duty which is exorbitant and it must be reduced as suggested by me.

With these words I move my amendments and request the Finance Minister to kindly consider this and accept them

DR RANEN SEN: Regarding the amendments in my name, Nos 73 to 81, I want to make a few points. In my speech on the Finance Bill I had said that this enhancement of Central excise duty on the patent drugs will completely ruin the common people

Let us examine what is the position in regard to the duty on drugs. The customs duty on drugs covered by GATT like ampicillin, etc., has been

*Moved with the recommendation of the President.

raised from 20 to 60 per cent. At the prevailing rate of 7.5 per cent excise duty the total realisation is Rs. 27 crores. Now, the additional duty, the hon. Minister has said, will yield Rs. 18 crores. So, it comes to Rs. 45 crores. Then, over and above that, there is a customs duty of 75 per cent on synthetic drugs and penultimate raw materials. The average duty is around 60 per cent and the total imports are Rs. 45 crores and on that there is the duty of 65 per cent. That means that it comes to Rs. 29 crores. Then if you add it to the earlier Rs. 45 crores the total comes to Rs. 74 crores. It means that quite a large amount of money is being realised from medicines on different accounts.

Now, the Government of India and the Chemical Fertiliser Ministry go on saying and the Government go on repeating, the Health Ministry goes on repeating, that the prices of drugs should be decreased. Now, firstly, the prices of all the inputs of the drugs are rising.

Alcohol and glycerine are common and very essential ingredients of medicine. Their prices are rising. The taxes are rising, but it is expected by the Government that the common man will get medicines at cheaper rates. This is a utopian idea. This is just to bluff the people that the Government of India is making a claim that the prices of the drugs will be lowered with the efforts of the Government. I say, it is impossible. Government has no control on the inputs and raw materials. Therefore, the prices are rising. 90 per cent of the medicines are patent drugs. Had it been an international patent medicine, I could have understood that.

Then I come to patent and proprietary medicines having some alcohol content. The prices of all tonics will rise because Waterbury Compound, Metatone and such other tonics which are prescribed by the doctors contain alcohol. So far as the drugs are concerned, these are taken by the rich and the poor as well. When a doctor prescribes it, the poor man's son has

also to use it. If he does not get it because of high price he dies. It is inhuman as the prices of all the tonics will immediately go up.

Secondly, here it is said—

“Medicinal preparations containing self-generated alcohol which are not capable of being consumed as ordinary beverages”.

Fine distinctions have been made and, therefore, the duties have been increased. It is a well known fact that Mrita Sanjeevni Sudha and Drakhasavs contain alcohol. All these ayurvedic tonics used by the people are prepared by the vaidis. Since there is alcohol content in them, the prices will go up.

In homoeopathic medicines too, the main ingredient is alcohol. I do not know much of homoeopathy, but this is what I have been told.

By taking a blanket decision, the Government is going to increase the prices of homoeopathic, allopathic, Unani and ayurvedic drugs.

Under it, 90 per cent of the drugs have been covered and only 10 per cent i.e., Vaccines and Sera will be left or exempted. It is inhuman and immoral on the part of the Government to raise the prices of the drugs. These should be lowered.

MR. SPEAKER: The Minister may reply.

SHRI VASANT SATHE (Akola): Before the Minister speaks. I may be allowed to speak, as I have not spoken. I think, it is the third reading.

MR. SPEAKER: It is not the third reading. You may speak later on.

SHRI C. SUBRAMANIAM: We have taken into consideration the various aspects that the hon. members have mentioned. They would find that this is only on 'patent or proprietary medicines'. If it is on the pharmacopoeial basis, then it does not come at all. That is what we want to see. On the basis of patent and

[Shri C. Subramaniam]

proprietary medicines, the same medicines which could be obtained at a lower price, because of these brand names they are able to get higher price. That is why they should be asked to pay high taxes. It is on that basis that it has been put.

As far as the other medicinal preparations (where alcohol contents are there) are concerned, this subject has reference to the taxation done for the States. Because these things should not be used with other ordinary things, and that is why we have increased this tax. There is therefore absolutely no case for accepting these amendments. As far as the poor people are concerned, they are not going to be affected at all by this.

MR. SPEAKER: I will now put amendments Nos. 16 to 27 moved by Shri Dinen Bhattacharyya, to the vote of the House.

Amendments Nos. 16 to 27 were put and negatived.

MR. SPEAKER: I will now put amendments Nos. 40 to 51 moved by Shri Ramavatar Shastri to the vote of the House.

Amendments Nos. 40 to 51 were put and negatived.

MR. SPEAKER: There are amendments Nos. 73 to 81 moved by Dr. Ranen Sen and amendment No. 82, moved by Shri Ramavatar Shastri. May I put all of them together to vote?

DR. RANEN SEN: Sir, please put amendment No. 73 separately to vote.

MR. SPEAKER: All right. I will do so. I will now put the rest of the amendments to vote. I am now putting amendments Nos. 74 to 81 moved by Dr. Ranen Sen and amendment No. 82 moved by Shri Ramavatar Shastri to the vote of the House.

Amendments Nos. 74 to 81 and 82 were put and negatived.

MR. SPEAKER: The question is:

Page 77, lines 13 to 16,—

for "Twenty per cent *ad valorem* or rupees three and seventy-five paise"

substitute—

"One per cent *ad valorem* or thirty-five paise" (73)

The Lok Sabha divided.

Division No. 5]

[13.16 hrs.

AYES

Bhattacharyya, Shri Dinen
Bhattacharyya, Shri Jagadish
Chandrappan, Shri C. K.
Goswami, Shrimati Bibha Ghosh
Gupta, Shri Indrajit
Pandey, Shri Sarjoo
Roy, Dr. Saradish
Sen, Dr Ranen
Shastri, Shri Ramavatar
Yadav, Shri G. P.

NOES

Achal Singh, Shri
Agrawal, Shri Shrikrishna
Ahrwar, Shri Nathu Ram
Ambesh, Shri
Arvind Netam, Shri
Aziz Imam, Shri
Besra, Shri S. C.
Bhagat, Shri H. K. L.
Bhatia, Shri Raghunandan Lal
Bhuvarahan, Shri G.
Bist, Shri Narendra Singh
Brahmanandji, Shri Swami
Brij Raj Singh-Kotah, Shri
Chandrakar, Shri Chandulal
Chandrika Prasad, Shri
Chaudhary, Shri Nitiraj Singh
Chavan, Shrimati Premalal
Chavan, Shri Yashwantrao
Chikkalingaiah, Shri K.

Daga, Shri M. C.
 Dalbir Singh, Shri
 Damani, Shri S. R.
 Darbara Singh, Shri
 Das, Shri Dharnidhar
 Daschowdhury, Shri B. K.
 Dhamankar, Shri
 Dhillon, Dr. G. S.
 Dhusia, Shri Anant Prasad
 Dinesh Singh, Shri
 Dumada, Shri L. K.
 Godara, Shri Manj Ram
 Ishaque, Shri A. K. M.
 Jadeja, Shri D. P.
 Jaffer Sharief, Shri C. K.
 Jha, Shri Chiranjib
 Joshi, Shrimati Subhadra
 Kailas, Dr.
 Kamble, Shri T. D.
 Kaul, Shrimati Sheila
 Khan, Shri I. H.
 Kotoki, Shri Liladhar
 Krishnan, Shri G. Y.
 Laskar, Shri Nihar
 Mahajan, Shri Vikram
 Mahajan, Shri Y. S.
 Majhi, Shri Gajadhar
 Marak, Shri K.
 Mehta, Dr. Mahipatray
 Mirdha, Shri Nathu Ram
 Mishra, Shri Bibhuti
 Mohammad Tahir, Shri
 Mohammad Yusuf, Shri
 Negi, Shri Pratap Singh
 Oraon, Shri Tuna
 Pahadia, Shri Jagannath
 Painuli, Shri Paripoornanand
 Pandey, Shri Krishna Chandra
 Pandey, Shri Sudhakar
 Paokai Haokip, Shri
 Parthasarathy, Shri P.
 Paswan, Shri Ram Bhagat
 Patel, Shri Arvind M.
 Patel, Shri R. R.

Pradhan, Shri Dhan Shah
 Qureshi, Shri Mohd. Shafi
 Raghu Ramaiah, Shri K.
 Rai, Shri S. K.
 Rai, Shrimati Sahodrabai
 Raj Bahadur, Shri
 Ram Surat Prasad, Shri
 Rao, Shri P. Ankineedu Prasada
 Rao, Shri Pattabhi Rama
 Rathia, Shri Umed Singh
 Raut, Shri Bhola
 Reddi, Shri P. Antony
 Reddy, Shri K. Kodanda Rami
 Reddy, Shri M. Ram Gopal
 Reddy, Shri P. V.
 Rohatgi, Shrimati Sushila
 Salve, Shri N. K. P.
 Samanta, Shri S. C.
 Sangliana, Shri
 Sant Bux Singh, Shri
 Sarkar, Shri Sakti Kumar
 Sathe, Shri Vasant
 Satish Chandra, Shri
 Satpathy, Shri Devendra
 Savant, Shri Shankerrao
 Shailani, Shri Chandra
 Shambhu Nath, Shri
 Sharma, Shri A. P.
 Shastri, Shri Sheopujan
 Shukla, Shri Vidya Charan
 Sohan Lal, Shri T.
 Stephen, Shri C. M.
 Subramaniam, Shri C.
 Swaran Singh, Shri
 Tiwari, Shri Chandra Bhal Mani
 Tulsiram, Shri V.
 Vekaria, Shri
 Vikal, Shri Ram Chandra
 Yadav, Shri Chandrajit

MR. SPEAKER: The result of the division is:

Ayes: 10; Noes: 102

The motion was negatived.

businessmen and monopolists to help the country to lift its economy. He said that they are on trial and the ball is in their court and the country wants to see whether they want to play the game. Sir, on what basis he is putting on this optimistic look? It is about two months since the budget proposals were put forward and I would have expected him to tell us whether whatever developments have taken place during these two months between the presentation of the budget proposals and the consideration of the Finance Bill justify the kind of optimism which he has placed in the private sector. Already the newspapers and the economic journals are discussing the so-called mystery of the whole-sale price index showing a 2 to 3 per cent rise. Even since 30th April the index of manufactured commodities has shown an increase of 3 per cent. This budget was hailed in the beginning by many people as though it is going to have de-flationary effect instead of inflationary effect because it is for the first time that there is big reduction in taxes—both direct and indirect—but what do we find! In spite of the fact that there has been a bumper crop of foodgrains and we have built up a substantial buffer-stock, in spite of the fact that procurement, according to the Government, is going very well, in spite of the fact that there has been almost a bumper crop of oilseeds, why is it that the wholesale price index has begun to rise again? It may be argued that it is just a small and temporary shift. But in our minds there are misgivings. This may be the beginning of a new trend if in spite of increased production—both in the private and the public sector—this 2 to 3 per cent rise has come about during this period of two months. It only means—as far as I can understand—that the whole structure of the budget proposals and the philosophy that has guided it has encouraged those people who control marketing operations in this country or who in the past dominated the entire market economy by their methods of speculation, etc. These people have again become encouraged to step up some of their activities which are

not being dealt with now as they were at the beginning of the Emergency. Already the price of vanaspati is going up. Already the price of oil has gone up. Sir, huge stocks worth several lakhs of rupees were unearthed the other day in Gujarat. Already there are reports in the Press that smuggled goods which disappeared have begun to re-appear again in the country. And there can be no explanation of this except that this class is being pampered by the Government because they think that only by tampering it, they will stimulate further investment and encourage them to produce more. These people have never agreed. They don't believe in this. They believe in their profits, nothing else. They have never accepted this philosophy. They have always been trying to have an artificially low production so that they can keep the price high. Already during these two months, many private sector units have been closed down and again they are restricting production and they are keeping down the employment as well as utilisation of their capacity and at the same time have mounted a new drive and pressure on the Government for further concessions. During these two months, every one of those important Chambers of Commerce and Organisations—of the industrialists, from FICCI to the Indian Chamber of Commerce—have held conferences in the last few days and is that the response he expected it to be? Do they tell the Government 'Yes, now because of all these big concessions, you have given us, now for some time we should not go on pestering you with more demands, but we are going to put our shoulder to the wheel and see that full production and employment are mounted up'? That is not at all what they are doing. They have tasted blood and therefore, they are out now for more blood and they are demanding that more concessions must be given to them. There must be more relaxation of controls, there must be less restrictions on credit and they must be given so many more advantages and in the meantime they are seeing to it that the units which are under their control are not

businessmen and monopolists to help the country to lift its economy. He said that they are on trial and the ball is in their court and the country wants to see whether they want to play the game. Sir, on what basis he is putting on this optimistic look? It is about two months since the budget proposals were put forward and I would have expected him to tell us whether whatever developments have taken place during these two months between the presentation of the budget proposals and the consideration of the Finance Bill justify the kind of optimism which he has placed in the private sector. Already the newspapers and the economic journals are discussing the so-called mystery of the whole-sale price index showing a 2 to 3 per cent rise. Even since 30th April the index of manufactured commodities has shown an increase of 3 per cent. This budget was hailed in the beginning by many people as though it is going to have de-inflationary effect instead of inflationary effect because it is for the first time that there is big reduction in taxes—both direct and indirect—but what do we find! In spite of the fact that there has been a bumper crop of foodgrains and we have built up a substantial buffer-stock, in spite of the fact that procurement, according to the Government, is going very well, in spite of the fact that there has been almost a bumper crop of oilseeds, why is it that the wholesale price index has begun to rise again? It may be argued that it is just a small and temporary shift. But in our minds there are misgivings. This may be the beginning of a new trend if in spite of increased production—both in the private and the public sector—this 2 to 3 per cent rise has come about during this period of two months. It only means—as far as I can understand—that the whole structure of the budget proposals and the philosophy that has guided it has encouraged those people who control marketing operations in this country or who in the past dominated the entire market economy by their methods of speculation, etc. These people have again become encouraged to step up some of their activities which are

not being dealt with now as they were at the beginning of the Emergency. Already the price of vanaspati is going up. Already the price of oil has gone up. Sir, huge stocks worth several lakhs of rupees were unearthed the other day in Gujarat. Already there are reports in the Press that smuggled goods which disappeared have begun to re-appear again in the country. And there can be no explanation of this except that this class is being pampered by the Government because they think that only by tampering it, they will stimulate further investment and encourage them to produce more. These people have never agreed. They don't believe in this. They believe in their profits, nothing else. They have never accepted this philosophy. They have always been trying to have an artificially low production so that they can keep the price high. Already during these two months, many private sector units have been closed down and again they are restricting production and they are keeping down the employment as well as utilisation of their capacity and at the same time have mounted a new drive and pressure on the Government for further concessions. During these two months, every one of those important Chambers of Commerce and Organisations—of the industrialists, from FICCI to the Indian Chamber of Commerce—have held conferences in the last few days and is that the response he expected it to be? Do they tell the Government 'Yes, now because of all these big concessions, you have given us, now for some time we should not go on pestering you with more demands, but we are going to put our shoulder to the wheel and see that full production and employment are mounted up?' That is not at all what they are doing. They have tasted blood and therefore, they are out now for more blood and they are demanding that more concessions must be given to them. There must be more relaxation of controls, there must be less restrictions on credit and they must be given so many more advantages and in the meantime they are seeing to it that the units which are under their control are not

[Shri Indrajit Gupta]

allowed to function properly so that a kind of blackmail is imposed on the Government.

About Wealth Tax, I think it is a scandalous matter. The way the Wealth Tax has been reduced, there is no justification for it. Even if there is some justification, it can be argued by some people that by giving some facilities to manufacturers industrialists they may be encouraged to produce more. But to those who are holders of enormous amounts of wealth and assets and so on why they have given such huge concessions in wealth tax? We do not know where the resources are going to come from. We do welcome very much the big increase in plan outlay. That is a move in the correct direction. But as I said in my speech made earlier, if you order a nice suit of cloth, where is the cloth with which you can make that suit? Where are the resources going to come from to finance this huge plan outlay if on the one hand you reduce wealth tax so steeply and on the other you also reduce other taxes and duties so much on the private sector and the big business sector? Also he has not imposed very many new excise duties on the common man. Where are the resources going to come from? And in the end we will find that it will be impossible to fulfil these plan targets and once again we will have to think of postponing the finalisation of the Fifth Plan once again prices may begin to raise and burdens will come in the common man and therefore we feel that this whole strategy, the whole philosophy behind this thing is ill-conceived and it will not consolidate further the gains that we have achieved under the Emergency, but rather will undermine them, and I am afraid that this is all being done under the sustained and concerted pressure which has been exerted for months together on this Government by the big business houses and the Chambers and Commerce, FICCI and such other bodies.

Therefore, I am sorry to say that despite one or two positive things in this Finance Bill which we have already mentioned, as a whole, we can not accept this because this is a very dangerous strategy. Therefore, our party will be compelled to record its vote against this Bill.

SHRI VASANT SATHE (Akola): Sir, the main point that I would like to make is that while we are having this marginal economy the effective market is being done by the three-crore people and every time when there is a little surplus we become panicky and every time when there is a little shortage, we also become panicky. This is the present position of our economy. Your budget is aimed at giving a boost to production by concessions. I wish you godspeed and all luck and hope that the industry will respond and will achieve your production target. But what I am eager to know is now we are going to create greater purchasing power and consumer goods for the remaining 57-crore of our population. For the programme spelt out in the budget for the growth of agro industries, a paltry sum of Rs. 12 crores has been provided, which is not enough to achieve the objective. If reduction in wealth tax is going to enable you to get this wealth ploughed back to the rural areas for industrial growth, I can understand, I do not know what you have in your mind.

You have suggested this new scheme of investment allowance replacing the original development rebate, which was discontinued.

MR. SPEAKER: At this stage, you are going to back to the clauses. The House has already passed them.

SHRI VASANT SATHE: What I am suggesting is an administrative matter. You have only to extend the schedule. You have included export-oriented industries. One industry which I have in mind is the iron ore export from Goa which is cent per cent export-oriented. It is not even export-oriented; it is

completely export. I do not understand and why this has not been included. When you want 60 per cent more export earnings to meet the requirements of Marmagoa port, would you please consider including it?

SHRI C. SUBRAMANIAM: I have listened carefully to Shri Indrajit Gupta's speech. There are very many points in it which are well taken. We are not unaware of the lurking dangers also. I want to assure him that we would be ever-watchful particularly on the price front and we shall try to see that again this monster of inflation does not raise its head. We will take the necessary measures and we will continuously review it. As far as the private sector is concerned, no doubt his point of view is to a certain extent justified, particularly taking into account the demands made by FICCI even after the budget concessions were given. But I suppose it has become a habit and therefore, however much we may give, they would ask for a little more. I hope it is only a formality of asking for more and taking advantage of all the concessions that have been given, I hope and trust they would respond to the situation. If they do not it is not as if we have no remedy at all.

About the other point made by Mr. Sathe about the mining industry, investment allowance is for future investments, I think mining is now completely reserved for the public sector and therefore, there is no question of giving investment allowance to the private sector for investment in the mining industry.

MR. SPEAKER: The question is: "That the Bill, as amended, be passed."

The Lok Sabha divided:

Division No. 6] [13.36 hrs.

AYES

Agrawal, Shri Shrikrishna
Ahirwar, Shri Nathu Ram

Ambesh, Shri
Arvind Netam, Shri
Aziz Imam, Shri
Barman, Shri R. N.
Bhagat, Shri H. K. L.
Bhatia, Shri Raghunandan Lal
Bhuvarahan, Shri G.
Bist, Shri Narendra Singh
Brahmanandji, Shri Swami
Chandrakar, Shri Chandulal
Chandrika Prasad, Shri
Chaudhari, Shri Amarsinh
Chaudhary, Shri Nitiraj Singh
Chavan, Shrimati Premalabai
Chavan, Shri Yeshwantrao
Chikkalingaiah, Shri K.
Daga, Shri M. C.
Dalbir Singh, Shri
Damani, Shri S. R.
Darbara Singh, Shri
Das, Shri Dharnidhar
Daschowdhury, Shri B. K.
Dhamankar, Shri
Dhillon, Dr. G. S.
Dhusia, Shri Anant Prasad.
Dinesh Singh, Shri
Dumada, Shri L. K.
Hari Singh, Shri
Ishaque, Shri A. K. M.
Jadeja, Shri D. P.
Jaffer Sharief, Shri C. K.
Jha, Shri Chiranjib
Joshi, Shrimati Subhadra
Kailas, Dr.
Kaul, Shrimati Sheila
Khan, Shri I. H.
Kotoki, Shri Liladhar
Krishnan, Shri G. Y.
Laskar, Shri Nihar

Mahajan, Shri Vikram
 Mahajan, Shri Y. S.
 Majhi, Shri Gajadhar
 Mandal, Shri Jagdish Narain
 Mandal, Shri Yamuna Prasad
 Mehta, Dr. Manojkumar
 Mirdha, Shri Nathu Ram
 Mishra, Shri Bibhuti
 Mohammad Tahir, Shri
 Mohammad Yusuf, Shri
 Negi, Shri Pratap Singh
 Orson, Shri Tuna
 Pahadia, Shri Jagannath
 Painuli, Shri Paripoornanand
 Pandey, Shri Krishna Chandra
 Pandey, Shri Sudhakar
 Paokai Haokip, Shri
 Parthasarathy, Shri P.
 Paswan, Shri Ram Bhagat
 Patel, Shri R. R.
 Pradhan, Shri Dhan Shah
 Qureshi, Shri Mohd. Shafi
 Raghu Ramiah, Shri K.
 Rai, Shri S. K.
 Rai, Shrimati Sahodrabai
 Raj Bahadur, Shri
 Rajdeo Singh, Shri
 Ram Surat Prasad, Shri
 Ram Swarup, Shri
 Rao, Shri P. Ankineedu Prasada
 Rao, Shri Pattabhi Rama
 Rathia, Shri Umed Singh
 Reddi, Shri P. Antony
 Reddy, Shri K. Kodanda Rama
 Reddy, Shri P. V.

Salve, Shri N. K. P.
 Samanta, Shri S. C.
 Sangliana, Shri
 Sant Bux Singh, Shri
 Sathu, Shri Vasant
 Satish Chandra, Shri
 Satpathy, Shri Devendra
 Shailani, Shri Chandra
 Sharma, Shri A. P.
 Sharma, Shri Nawal Kishore
 Shastri, Shri Shashipujan
 Shivnath Singh, Shri
 Shukla, Shri Vidya Charan
 Sohan Lal, Shri T.
 Stephen, Shri C. M.
 Subramaniam, Shri C.
 Swaran Singh, Shri
 Tiwari, Shri Chandra Bhai Mani
 Tula Ram, Shri
 Tulsiram, Shri V.
 Unnikrishnan, Shri K. P.
 Vikal, Shri Ram Chandra
 Yadav, Shri Chandrajit
 NOES
 Banerjee, Shri S. M.
 Bhattacharyya, Shri Dinen
 Bhattacharyya, Shri Jagdish
 Bhattacharyya, Shri S. P.
 Chandrappan, Shri C. K.
 Garcha, Shri Devinder Singh
 Goswami, Shrimati Bibha Ghosh
 Gupta, Shri Indrajit
 Joarder, Shri Dinesh
 Pandey, Shri Sarjoo
 Ram Deo Singh, Shri

Reddy, Shri B. N.

Sen, Dr. Ranen

Shastri, Shri Ramavatar

MR. SPEAKER: The result* of the division is:

Ayes: 99; Noes; 14.

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: We now adjourn to meet again at 14.45 hours. 13.40 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Forty-five Minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled, after Lunch at Forty-eight Minutes past Fifteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

COAL MINES (NATIONALISATION)
AMENDMENT BILL

MR. DEPUTY SPEAKER: We take up the Coal Mines (Nationalisation) Amendment Bill.

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI K. C. PANT): I beg to move:

"That the Bill further to amend the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973, be taken into consideration."

Sir, as the House knows, the coal mines in the country were nationalized in two phases. Firstly, the coking coal mines were nationalized in 1971 after taking over their management in the first place; and later, the management of non-coking coal mines was taken over; and that too, was followed by the nationalization of non-coking coal mines. And the intention behind these steps was that coal mines should be owned and managed by the public sector, except that the State Governments could also run the coal mines through their corporations. The Central Government could set up its cor-

porations for managing the coal mines; and the private sector steel plants could also own their coal mines. And it was this broad provision or set of provisions under which the coal mines industry has been functioning in the last few years. Sir, before the coking and non-coking mines were nationalized, all the available records were scrutinized, to determine the number of coal mines.

According to the records which were available with the State Government as well as with the Central Government, in all 925, mines were nationalized, that is, 214 coking coal mines and 711 non-coking coal mines. Subsequently, a number of cases came to light mainly in Bihar in which there were private individuals holding leases of coal mines, and these individuals started operating these mines and extracting coal without proper authorisation. And ultimately we found that in Bihar alone about 450 lease holders were identified. We did not know if this was the total number.

I had a discussion with the Government of Bihar. I tried to ascertain how many cases of private leases escaped notice at the time of nationalisation because this is a problem which I have inherited. I was not aware of the facts at that time. I tried to check the records and history of nationalisation as to how many cases were left out. I found that there were mines with private parties which escaped being identified when the Central Government took over mines at the time of nationalisation. I also found that there were leases granted, by *ex-zamindars* or *rajahs*, *ex-rajahs* before the commencement of the Mines and Mineral Regulation and Development Act 1957, of which full records were not available in the records of the State Government. So, naturally, the details not being available with the State Government, these also got left out. Then there were idle or dormant leases covering closed or aban-

*The following Members also recorded their votes for AYES:— Sarvashri Shankarrao Savant and Tarkeshwar Pandey.